।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

● वर्ष-5
● अंक-233
रायपुर, रविवार
17 मई 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

पेज-8› आकाशवाणी के 90 वर्ष पर भव्य...

नीदरलैंड में प्रवासी भारतीयों से पीएम मोदी का संवाद

भारत इनोवेशन पॉवर है : मोदी

एम्स्टर्डम (नीदरलैंड)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड की यात्रा पर हैं। उन्होंने द हेग में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। इस दौरान अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, इतना प्यार और उत्साह... सच कहूं तो कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसे लग रहा है कि जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है।

भारतीय समुदाय के योगदान पर गौरवान्वित होते हुए पीएम मोदी ने कहा, आप नीदरलैंड के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो आपकी देन हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता और सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान भारत की विश्व को देन और भारतीय संस्कृति का उल्लेख करते हुए आगे कहा, यहां बैठे अनेक परिवारों की कहानी प्रवासन की कहानी नहीं, यह सांस्कृतिक आस्था के बीच तमाम संघर्षों के बीच प्रगति की कहानी है। उस दौर में तब किसी ने सोचा नहीं था कि दो महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़ गए, लेकिन कुछ चीजें उनके साथ रहीं, अपनी मिट्टी की

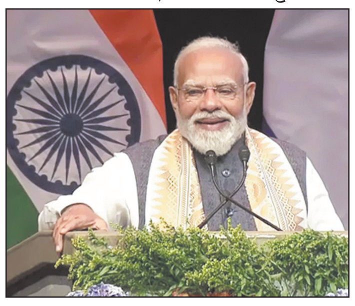

खशबू, त्योहार की संस्कृति, भजन की धुनें और पूर्वजों के संस्कार। समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गईं लेकिन भार की विविध संस्कृति अपने लोगों के दिलों में धड़कता है।

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा- बीते वर्षों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है, उससे भी 11 गुना अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्यूफेक्चरर है। इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है। आज का भारत इनोवेशन पॉवर है। आज हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ये भारतीयों के इनोवेशन का बहुत बड़ा प्रमाण है। भारत में चिप निर्माण, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अभी भारत में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट पर काम चल रहा है। इनमें से दो प्लांट में उत्पादन भी शुरू हो चुका है। यानी अब चिप भी, भारत में डिजाइन, भारत में निर्मित होगी।प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों से संवाद में कहा- आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले जी-20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बड़ी आकांक्षाओं से भरा है और निकट भविष्य में वह ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहेगा और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का भी बड़ा सपना देखेगा। भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बनना चाहता है।इस दौरान पीएम मोदी ने कहा मैं बहुत छोटी आयु में ही देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरे परिवार बन गए। अहम् से वयम् का रास्ता चुन लिया। फिर आपका सुख ही मेरा सुख बन गया और आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया।

नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का भारत बड़े सपने देखना चाहता है। इसकी आकांक्षाएं असीमित हैं और इसलिए यह स्टार्टअप इकोसिस्टम में योगदान देना चाहता है। आज देश कह रहा है- हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, हमें सबसे अच्छा चाहिए, हमें सबसे तेज चाहिए। इसलिए जब भारत में आकांक्षाएं असीमित हैं, तो प्रयास भी असीमित हो रहे हैं। आज भारत का युवा आकाश छूना चाहता है।

हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा फैसले की सराहना की, जब उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पहली बार सत्ता संभाली थी।

मोदी के काफिले में कटौती पर भड़के कई सुरक्षा विशेषज्ञ

प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौते को बताया देशहित के खिलाफ

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने सुरक्षा काफिले का आकार घटाने के फैसले ने देश में नई बहस छेड़ दी है। एक ओर इसे ईंधन बचत और सादगी का संदेश माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई पूर्व पुलिस अधिकारियों, खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बताया है। उनका कहना है कि मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता।

रॉ के पूर्व सचिव सामंत गोयल ने इस निर्णय पर चिंता जताते हुए कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा माहौल अत्यंत अस्थिर और संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देशों में भी शीर्ष नेताओं पर हमलों की घटनाएं हो चुकी हैं। भारत के खिलाफ सक्रिय कई आतंकी और शत्रुतापूर्ण तत्व लगातार साजिशें रच

रहे हैं, विशेषकर पड़ोसी देश से प्रायोजित आतंकी गतिविधियां अब भी गंभीर खतरा बनी हुई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को कम करने की बजाय और मजबूत करने की जरूरत है।

सामंत गोयल ने कहा कि आज सुरक्षा खतरों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ड्रोन और दूर से निशाना साधने वाली अत्याधुनिक बंदूकों जैसे खतरे सामने आ चुके हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का लगातार पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और सुरक्षा घेरे को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कमी देशहित में नहीं मानी जा सकती।उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा किसी प्रकार का प्रतिष्ठा चिन्ह नहीं होती, बल्कि खतरे के आकलन के आधार पर तय की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के समय से ही लगातार खतरे मिलते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय गिरोहों और कट्टरपंथी आतंकी संगठनों की नजर लंबे समय से उन पर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री के काफिले में यदि बहुत कम वाहन होंगे तो विरोधी ताकतों के लिए निशाना साधना आसान हो सकता है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री की कार और उनकी गतिविधियों को लेकर गोपनीयता बनाए रखना बेहद आवश्यक है।

वहीं जम्मू-कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं ईंधन बचत के लिए कदम उठा सकता है तो आम नागरिकों को भी आगे आना चाहिए। हालांकि उन्होंने भी दोहराया कि प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे अधिक खतरे वाले नेताओं में शामिल हैं और उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है और उनकी सेवा करना ही सरकार का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार सरकार की जनता तक सीधी पहुंच और संवेदनशील कार्यशैली का प्रतीक है। 1 मई से प्रारंभ हुआ सुशासन तिहार 10 जून तक संचालित होगाए जिसके माध्यम से प्रदेशभर में आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

सीईसी की नियुक्ति में न्यायिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं

केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

नई दिल्लीं संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में न्यायिक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं करता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ये बात कही है। सरकार ने कहा कि न्यायपालिका के किसी सदस्य को शामिल करना एक विधायी विकल्प है, न कि सांविधानिक अनिवार्यता। यह हलफनामा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दाखिल किया गया है।

वर्ष 2023 का यह अधिनियम दो जनवरी 2024 को लागू हुआ था। यह निर्धारित करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के

नेता शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून ने तीन-सदस्यीय चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से प्रतिस्थापित कर दिया है।

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान चुनाव आयोग की नियुक्ति समितियों में न्यायिक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं करता है। न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य का समावेश एक विधायी विकल्प है, न कि एक सांविधानिक अनिवार्यता। सरकार का तर्क है कि यह सुझाव कि नियुक्तियों को मान्य करने के लिए न्यायिक भागीदारी आवश्यक है, शक्तियों के पृथक्करण और अनुच्छेद 324 के तहत संसद की भूमिका की गलत समझ है।हलफनामे में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता उसकी सांविधानिक स्थिति, कार्यकाल की सुरक्षा, पद से हटाने के लिए सुरक्षा उपायों और उसके कार्यों व भत्तों की वैधानिक सुरक्षा से उत्पन्न होती है। 2023 का अधिनियम इन विशेषताओं को बनाए रखते हुए उनकी नियुक्ति में प्रक्रियात्मक पारदर्शिता जोड़ता है। सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि अधिनियम के लागू होने से पहले की गई चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि तब कार्यपालिका के पास नियुक्तियां करने की विशेष शक्ति थी। हलफनामे में कहा गया है कि ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है कि केवल राष्ट्रपति के अधिकार के तहत नियुक्तियों के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हुए हों।

प्रमुख समाचार

अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर डोला सेन ने किया बचाव

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज किए जाने के बाद टीएमसी सांसद डोला सेन ने विश्वास व्यक्त किया कि सत्य और न्याय की जीत होगी। सेन की टिप्पणियों से एक दिन पहले, 15

मई को बिधाननगर उत्तर साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि बनर्जी ने राजनीतिक रैलियों और चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ, धमकी भरे और उत्तेजक भाषण दिए, जिससे हिंसा भड़की, शत्रुता को बढ़ावा मिला और जन शांति भंग हुई। शिकायतकर्ता, राजीव सरकार ने मार्च और अप्रैल के बीच महेशतला, आरामबाग, हरिंघाटा और नंदीग्राम में बनर्जी द्वारा दी गई रैलियों के भाषणों का जिक्र किया, जिनमें उन्होंने कथित तौर पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को धमकी दी और आक्रामक भाषा का प्रयोग किया।

डीएमके के हार की समीक्षा करेगी 38 सदस्यीय कमेटी

चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शनिवार को कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रवार जमीनी स्तर का आकलन करने के लिए 38 सदस्यीय समिति का गठन किया है। एक्स पर एक पोस्ट में स्टालिन ने कहा कि समिति के सदस्यों को पार्टी मुख्यालय के

प्रतिनिधियों के रूप में सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में भेजा जा रहा है ताकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भावनाओं को समझा जा सके। स्टालिन ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों के संबंध में, मैंने सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में जमीनी स्तर का अध्ययन करने के लिए 38 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। आज, उनके साथ अपनी बैठक के दौरान, मैंने इस अध्ययन को कैसे किया जाना चाहिए, इस बारे में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। और पार्टी के भीतर सुधारात्मक उपाय और बदलाव जून के अंत तक लागू कर दिए जाएंगे।

चेन्निथला को मनाने की कोशिश मिल सकती है गृह विभाग

नईदिल्ली। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में दरकिनार किए जाने से नाराज वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला को वी डी सतीशान मंत्रिमंडल में गृह और सतर्कता मंत्रालय का प्रभार दिया जाएगा। विरोध जताते हुए पार्टी की बैठकों से दूर रहने वाले चेन्निथला को मनाने के लिए, उच्च कमान ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को निर्देश दिया है कि

उन्हें उच्च-स्तरीय विभागों के साथ मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। सूत्रों के अनुसार, उच्च कमान का यह कदम पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह महत्वपूर्ण हस्तक्षेप उन खबरों के बीच आया है कि चेन्निथला मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं। हालांकि, उच्च कमान ने सतीशान को स्पष्ट कर दिया कि वरिष्ठता को देखते हुए चेन्निथला इस पद के लिए पूरी तरह योग्य हैं। सूत्रों के अनुसार, उच्च कमान ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को यह भी याद दिलाया कि चेन्निथला शीर्ष पद के दावेदारों में से एक हैं।

ईडी सरकार के इशारे पर चलती है : रॉबर्ट वाड्रा

नईदिल्ली। शिखोपुर भूमि सौदे मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बड़ा झटका लगा है। शनिवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दे दी। वाड्रा पहले जारी किए गए समन के अनुपालन में अदालत में पेश हुए थे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा के समक्ष हुई, जिन्होंने वाड्रा को जमानत

बांड जमा करने का निर्देश दिया। दिल्ली की अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राहत देते समय उन पर कोई अतिरिक्त शर्तें नहीं लगाई जा रही हैं। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा, मैं केवल जमानत बांड जमा करने के लिए कह रहा हूं, कोई अन्य रियायत नहीं। शिकोहपुर जमीन सौदे के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मुझे इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है। मुझे पता है कि ईडी सरकार द्वारा संचालित है और सरकार के निर्देशों पर ही चलती रहेगी। इसलिए ईडी की तरफ से यह उचित नहीं है।

डीएम पर विवादित टिप्पणी में आजम खां को दो साल की कैद

रामपुर। सपा नेता आजम खां को तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की कोर्ट ने दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान सपा नेता ने तत्कालीन जिलाधिकारी पर

आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आजम खां को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया। उधर, सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा बढ़ाने को लेकर दायर अपील पर शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू हुई। बचाव पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बहस की।

भारतीय न्यायपालिका की चर्चा सारी दुनिया में

सनत जैन

भारतीय न्यायपालिका को लंबे समय तक लोकतंत्र के सबसे विश्वसनीय स्तंभ के रूप में देखा जाता रहा है। दुनिया भर में भारत की न्याय व्यवस्था की चर्चा इसलिए होती थी क्योंकि यहां लिखित संविधान, स्थापित विधिक परंपराएं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा माना गया। न्याय की देवी की आंखों पर बंधी काली पट्टी इस बात का प्रतीक थी कि अदालतें बिना भेदभाव, केवल संविधान और कानून के आधार पर न्याय करेंगी। यही कारण था कि उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के अनेक ऐतिहासिक फैसलों ने भारतीय न्यायपालिका को वैश्विक सम्मान दिलाया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका के कामकाज को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। आलोचना के केंद्र में यह धारणा बनी है, कि अदालतें अब पहले जैसी निर्भीक और जनविश्वास की प्रतीक नहीं रह गई हैं। आम लोगों के बीच यह भावना गहराने लगी है कि कई संवेदनशील मामलों में सुनवाई और फैसलों का समय सरकारों की राजनीतिक सुविधा के अनुसार तय होता दिखाई देता है। न्यायपालिका का दायित्व केवल कानून की व्याख्या करना नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना भी है। यदि यही भरोसा कमजोर पड़ने लगे, तो लोकतंत्र की नींव भी प्रभावित होती है। एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने जनहित याचिका की अवधारणा को विस्तार देते हुए आम नागरिकों के लिए न्यायालयों के द्वार खोल दिए थे। पोस्टकार्ड और साधारण पत्रों के माध्यम से भी लोगों को न्याय मिलने लगा था। 1975 में इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करने वाला फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। उस दौर में अदालतों ने कई बार सरकारों के खिलाफ कठोर फैसले दिए और नागरिक अधिकारों की रक्षा की।

वर्तमान की बात करें तो आज की स्थिति कहीं अधिक जटिल दिखाई देती है। कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में

वर्षों तक सुनवाई लंबित रहती है। चुनाव, नागरिक अधिकार, जांच एजेंसियों की कार्रवाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक आधार पर बनाए गए कानूनों जैसे विषयों पर समयबद्ध फैसले न आने से न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठते हैं। यदि किसी मामले का निर्णय तब आए जब उसका प्रभाव समाप्त हो चुका हो, तो न्याय की सार्थकता भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि देरी से मिला न्याय भी न्याय नहीं रह जाता है। न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं। जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप, महाभियोग की जटिल प्रक्रिया और इस्तीफों के बाद कार्रवाई का समाप्त हो जाना लोगों के मन में असमंजस पैदा करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन भी उतना ही जरूरी है। लोकतंत्र में कोई भी संस्था आलोचना से ऊपर नहीं हो सकती। हाल के वर्षों में अदालतों में सुनवाई के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों ने भी बहस को जन्म दिया है। न्यायाधीशों की टिप्पणियां यदि सामाजिक या राजनीतिक रूप से पक्षधर प्रतीत हों, तो आम नागरिकों का विश्वास प्रभावित होता है। बेरोजगारी, पेपर लीक, लंबित नियुक्तियां और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर युवा वर्ग में पहले से ही असंतोष व्याप्त है। ऐसे समय में अदालतों से संवेदनशील और संतुलित दृष्टिकोण की अपेक्षा स्वाभाविक है।

यह भी याद रखने की जरूरत है कि संविधान ने न्यायपालिका को सबसे कमजोर नागरिक की रक्षा का दायित्व सौंपा है। विधायिका और कार्यपालिका स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली संस्थाएं होती हैं, जबकि आम नागरिक अक्सर उन्हीं से संघर्ष करते हुए अदालतों तक पहुंचता है। इसलिए न्यायपालिका का मूल उद्देश्य सत्ता की रक्षा नहीं, बल्कि संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा होना चाहिए। आज आवश्यकता न्यायपालिका को कठघरे में खड़ा करने की नहीं, बल्कि आत्ममंथन की है। न्याय में देरी, पारदर्शिता की कमी और बढ़ती अविश्वसनीयता जैसी चुनौतियों पर गंभीरता से विचार करना होगा। भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसका नैतिक अधिकार और जनविश्वास रहा है।

करोड़ों की सिटी बस सड़क से गायब, नई ई-बसों का पता नहीं

राजनांदगांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद रोज पहले खाड़ी युद्ध को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल-डीजल की किफायत के इस्तेमाल करते हुए जहां तक हो सके सार्वजनिक परिवहन सुविधा का इस्तेमाल करने की अपील की थी। लेकिन इसके अमलीजामा पहनाने में व्यवहारिक दिक्कत आ रही है, जिसमें राजनांदगांव जैसे शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवा का अभाव है। दस साल पहले शहर के लोगों को सुविधाजनक और सस्ती आवागमन सुविधा मुहैया कराने के लिए करीब पांच करोड़ रुपए की लागत से बीस बसें खरीदी गई थी। कुछ बसें शुरुआती दौर में चल भी रही थी। लेकिन संचालकों की मनमानी जिला प्रशासन पर भारी पड़ गई, और कोरोना संक्रमण के बाद चल रही कुछ बसें भी सड़क से गायब हो गई। कोरोना संक्रमण के बाद बंद पड़ी बसें अब तक नहीं चल पाई है। वर्तमान में कई बसें गायब हो गई हैं। पड़ताल करने पर पता चला कि आधा दर्जन बसें नया बस स्टैंड में खड़ी हैं, वही दो बसें पाताल भैरवी मंदिर हाइवे के सामने देखी गई। जबकि, अन्य बसों का पता नहीं है। कीमती बसों का संचालन जिला अर्बन कमेटी के देखरेख में किया जाना था। लेकिन वर्तमान में कमेटी को भी बसों की जानकारी नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस लापरवाही पर कार्यवाही तो दूर, इसके लिए जिम्मेदारी भी तय नहीं की गई हैं।

गेवरा खदान की सुरक्षा में चूक, सीआईएसएफ ने 12 संदिग्ध लोगों को पकड़ा

कोरबा। एसईसीएल गेवरा कोयला खदान में सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने खदान परिसर में अवैध रूप से घुसे 12 लोगों को पकड़ा। सभी के खिलाफ दीपका थाना में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस को सौंप दिया गया। निरीक्षक श्रद्धा देवांगन माहेश्वरी के नेतृत्व में सीआईएसएफ टीम ने खदान क्षेत्र में औचक जांच अभियान चलाया। यह जांच बी-2, ओल्ड दीपका और क्यू-कोल स्टॉक क्षेत्रों में केंद्रित रही। निरीक्षण में 12 व्यक्ति खदान परिसर में संदिग्ध हालत में घूमते मिले। पूछताछ में वे वैध पास या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। बिना अनुमति प्रवेश सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन है। खुले मुहाने की खदान में बाहरी लोगों का प्रवेश जानलेवा हो सकता है। इससे हादसे और कोयला चोरी का खतरा बना रहता है। सीआईएसएफ ने सभी 12 लोगों को हिरासत में लेकर दीपका थाना पुलिस को सौंपा। पुलिस उनके मकसद के बारे में पूछताछ कर रही है। गेवरा खदान देश की सबसे बड़ी ओपनकास्ट कोयला खदानों में से एक है। यहां अवैध प्रवेश और चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। कोयला चोरी, स्क्रैप चोरी या अन्य आपराधिक गतिविधि की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। दीपका थाना प्रभारी प्रेमचन्द्र साहू ने बताया कि सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। एसईसीएल गेवरा प्रबंधन घटना के बाद सतर्क हो गया है।

आस्था और परंपरा का संगम, नगर से गांव तक श्रद्धा से मनाई वट सावित्री पूजा

सारंगढ़। सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना का पर्व वट सावित्री पूजा इस बार भी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। नगर से लेकर सुदूर गांवों तक वट वृक्षों के नीचे महिलाओं की भीड़ रही। मंत्रोच्चार, लोकगीतों और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा-अर्चना की। सारंगढ़ जिला मुख्यालय सहित कोसीर गांव में दोपहर के समय वट सावित्री पूजा का मुख्य अनुष्ठान संपन्न हुआ। यहां सैकड़ों महिलाओं ने बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र होकर पूजा अर्चना की। सावित्री-सत्यवान की कथा सुनी और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। पूरे क्षेत्र में सुबह से ही बाजारों में पूजा सामग्री, मौली, सूत, फल-फूल और श्रृंगार की वस्तुओं की रौनक दिखी।

वट सावित्री पूजा का महत्व

हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले इस व्रत की मान्यता पौराणिक कथा सावित्री और सत्यवान से जुड़ी है। मान्यता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से वापस लाकर पतिव्रता धर्म की शक्ति का परिचय दिया था। तभी से महिलाएं इस दिन व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। वट वृक्ष की पूजा करने से सुख, समृद्धि, संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, बल्कि यह नारी शक्ति, धैर्य और समर्पण का भी प्रतीक है।

सारंगढ़ जिले में दिखा उत्साह

सारंगढ़ नगर के प्रमुख मंदिरों और कोसीर गांव के जीवन दायिनी बांधा तालाब के वट वृक्षों के आसपास सुबह 6 बजे से ही महिलाओं का आना शुरू हो गया था। पारंपरिक लाल-सफेद साड़ी, चूड़ी और सिंदूर से सजी महिलाओं ने वट वृक्ष को कच्चे सूत से 108 बार बांधकर परिक्रमा की।

केंद्रीय समिति के सदस्य नरहरि ने पत्नी संग किया सरेंडर

जगदलपुर। माओवादी संगठन को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय समिति के सदस्य और 20 लाख रुपये के इनामी माओवादी पसुनूरी नरहरि ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि नरहरि, जिसे संतोष के नाम से भी जाना जाता है, तेलंगाना के हनमकोंडा का रहने वाला है। वह लंबे समय से झारखंड में माओवादियों की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। नरहरि की पकड़ संगठन में काफी मजबूत मानी जाती थी। वह बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी और पूर्वी क्षेत्रीय ब्यूरो में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुका है। आत्मसमर्पण की बड़ी वजह उसका लगातार खराब होता स्वास्थ्य बताया जा रहा है। इसी के चलते उसने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर करने का फैसला लिया। खास बात यह है कि नरहरि ने अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी जोबा उर्फ पूनम के साथ आत्मसमर्पण किया है, जो खुद क्षेत्रीय समिति की सदस्य बताई जा रही है। पुलिस के लिए इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि नरहरि लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 15 इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार वहीं बुधवार को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 15 इनामी नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। अधिकारियों के मुताबिक, गढ़चिरौली जिले में 11 और कांकेर में चार नक्सलियों ने पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक के समक्ष सरेंडर कर दिया। इन सभी पर 82 लाख और 23 लाख रुपये का इनाम था। अधिकारियों के मुताबिक, बड़ी संख्या में नक्सली खोखली माओवादी विचारधारा से निराश होकर मुख्यधारा में लौटने को तैयार हो रहे हैं। गढ़चिरौली जिले में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला के समक्ष जब 11 नक्सलियों ने हथियार डाले, तब उनमें से चार वर्दी में थे। इसमें मंडल समिति के सदस्य 57 वर्षीय रमेश लेकामी, 35 वर्षीय भीमा कोवासी, पार्टी मंच समिति के सदस्य 41 वर्षीय पोरिये गोटा, 32 वर्षीय रतन ओयम, 30 वर्षीय कमल वेलाडी (30) हैं। ये सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इसके अलावा क्षेत्र समिति के सदस्यों में 36 वर्षीय पोरिये वेलाडी, 35 वर्षीय रामजी पुंगती, 19 वर्षीय सोनू काटो, 22 वर्षीय प्रकाश पुंगती, 21 वर्षीय सीता पालो और 23 वर्षीय साईनाथ माडे शामिल हैं, जो कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे। इसके अलावा कांकेर जिले में कुल 23 लाख रुपए के इनामी चार नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनकी पहचान काजल उर्फ रजीता वेड़दा, मंजूला उर्फ लक्ष्मी पोटाई, विलास उर्फ चैतु उसेंडी और रामसाय उर्फ लखन मर्रापी के रूप में हुई है।अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कई नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कैडर को प्रोत्साहन स्वरूप 50-50 हजार रुपये की तत्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई। अब तक सरेंडर छत्तीसगढ़ में पिछले दो साल में राज्य में 2380 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2022 से अब तक 146 कट्टर नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं।

आप नेता शारीरिक शोषण के आरोप में गिरफ्तार जान से मारने दी थी धमकी

बीजापुर। कोतवाली थाना पुलिस ने आम आदमी पार्टी के बीजापुर जिला अध्यक्ष सतीश मंडावी को गिरफ्तार किया है। आप जिला अध्यक्ष सतीश मंडावी पर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगा है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश किया है। आरोपी नेता पर पीड़िता ने धोखे से घर बुलाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसे नेता ने वोटर कार्ड और अटल आवास का दस्तावेज बनाने के बहाने बुलाया। जहां जबरन उसके साथ गलत काम किया गया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने उसे धमकाया भी कि अगर वो घटना के बार में किसी को बताएगी, तो उसे वो जान से मार देगा। घटना के बाद पीड़िता सीधे सखी सेंटर पहुंची और उसने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी वहां मौजूद लोगों को दी। परिजनों और सखी सेंटर के लोगों की मदद से पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ, भारतीय न्याय संहिता (क्नहस्र) की धारा 64(1), 64(2)(द्व) एवं 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता एवं गवाहों के विस्तृत कथन दर्ज किए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य सहित अन्य आवश्यक सबूत जुटाए गए।

जगदलपुर में सुहागिनों ने निर्जला व्रत कर पति की लंबी उम्र की कामना

जगदलपुर। शनिवार को सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ वट सावित्री का व्रत रखा। इस दौरान महिलाओं ने निर्जला उपवास रखते हुए बरगद के पेड़ की विधि-विधान से पूजा की और पेड़ में धागा बांधकर अपने सुहाग की दीर्घायु की प्रार्थना की। पूजा के अवसर पर कथा सुनकर महिलाओं ने मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना की।

वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत पति-पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाने के लिए कठोर तप, समर्पण और अटूट दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। इसी कथा के स्मरण में यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पतियों के दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करती हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष में ही सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। वट वृक्ष को भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे दीर्घायु, स्थिरता और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रमुख देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं इस दिन वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं।

पेट्रोल-डीजल संकट और पीएम की अपील पर अरुण वोरा का तंज

कहा- क्या चुनाव के समय पानी से चल रही थी गाड़ियां

बालोद- ईंधन की कमी और बिगड़ते हालातों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में फर्क अब समझ में आ रहा है। विदेश नीति कहते-कहते सरकार आज जनता को रोड में लाइन लगाने पर मजबूर कर चुकी है। आपको बता दें कि दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा बालोद जिला कांग्रेस कमेटी राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पूर्व विधायक अरुण वोरा ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के हर ज्वलंत मुद्दों को समय-समय पर उठाते रहे हैं। इस तरह से स्थितियां बिगड़ने शुरू हुई तो राहुल गांधी जी ने 3 महीने पहले ही आगाह कर दिया था कि आर्थिक भूचाल आने वाले हैं। केंद्र सरकार ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और आज देख सकते हैं कि किस तरह स्थितियां बिगड़ चुकी है। यह खराब विदेश नीति का ही नतीजा है कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं उन्होंने कहा कि जिओ कंपनी के सभी पेट्रोल पंप में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अन्य पंप में 2-3 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए अब मोदीजी लोगों को ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 सूत्रीय अपील किए हैं तो यह अपील किसी के गले अब नहीं उतर रही है। पूर्व विधायक अरुण वोरा ने बताया कि जब विधानसभा के चुनाव थे तब सरकार को इन सब विषयों की जानकारी हो गई थी लेकिन सरकार ने मामले को दबा कर रखा था। जैसे ही चुनाव के परिणाम आए तो अब सरकार का नाटक शुरू हो चुका है और इस तरह लोगों के माथे पर अपनी सारी परेशानियां सरकार थोप रही है। अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे थे तब रैलियां निकाल रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, तब पेट्रोल डीजल का ख्याल उन्हें नहीं आया। आगे वोरा ने कहा कि मोद जी अब कह रहे हैं ई रिक्शा में घूमे, साइकिल चलाएं, अब कह रहे काफिला कम करो, कारकेट कम करो। पहले क्या गाड़ियां पानी से चल रही थी क्या, यह सब मुद्दे हैं जो हम सरकार के पास रखते हैं और जनता को भी समझनी चाहिए कि सरकार आज किस स्थिति में खड़ी है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

शादी की खुशियों में पसरा मातम, झटके में खत्म हो गई जिदंगी

बालोद। रफ्तार के कहर ने एक और घर के चिराग से बुझा दिया। घटना राजहरा की है, जहां शनिवार सुबह मुर्गा बाजार इलाके में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़े युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि युवक की मौके पर ही तड़पकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक युवक पास के गांव में शादी समारोह में शामिल होने आया था। विवाह वाले घर में जैसे ही हादसे की खबर पहुंची, वहां पर मातम पसर गया। पीड़ित के परिवार वालों ने बताया कि मृतक युवक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुआ था। घर में शादी के बाद का प्रोग्राम चल रहा था। नाच गाने के बाद युवक थोड़ी देर के लिए सड़क की ओर निकला। तभी तेज गति से आ रहे वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपी वाहन चालक गाड़ी सहित मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद अब वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद नाराज मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर दिया।

आरंग में भारी तनाव, गौ सेवक पर मारपीट का आरोप

आरंग। आरंग थाना में आज उस समय स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई, जब सैकड़ों की संख्या में सतनामी समाज के लोग आरंग थाने के बाहर एकत्र हुए और उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। समाज का आरोप है कि कथित गौ सेवक गोल्डी शर्मा और उसके साथियों ने समाज के एक व्यक्ति के साथ न केवल दुर्व्यवहार किया, बल्कि पुलिस थाने के सामने ही उसके साथ मारपीट की। वर्तमान में आरंग थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मिली जानकारी के अनुसार, कुछ दिनों पहले कथित गौ सेवकों ने ग्राम गुदगुदा में भैंसों से भरे एक वाहन को पकड़ा था। इसी मामले को लेकर विवाद लगातार बढ़ता गया। आरोप है कि आज इसी बात पर कथित गौ सेवक गोल्डी शर्मा ने ग्राम गुदगुदा निवासी बलराम कुर्रे (सतनामी समाज के सदस्य) के साथ सरेआम गाली-गलौज की और उसके साथ मारपीट की। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गोल्डी शर्मा द्वारा बलराम कुर्रे के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करते देखा जा सकता है।

महुआ पेड़ की छांव में जनसमस्याओं का दरबार

कोरिया। सोनहत जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पोड़ी में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण एवं समाधान शिविर का आयोजन किया गया। महुआ पेड़ की छांव में खुले मैदान में आयोजित इस शिविर में 12 गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए और अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए। शिविर में लगभग 500 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 38 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान गांव स्तर पर करने की पहल को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य प्रशासन को गांव-गांव तक पहुंचाकर आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि कई बार ग्रामीणों तक शासन की योजनाओं की सही जानकारी नहीं पहुंच पाती, इसलिए सभी विभागों के स्टॉल एक ही स्थान पर लगाए गए हैं।

सरगुजा में क्रिकेट संघ के सचिव पर लगे मनमानी के आरोप

सरगुजा। क्रिकेट खिलाड़ी आशुतोष प्रजापति के साथ ही कई अन्य जूनियर खिलाड़ियों के परिजन संघ के सचिव से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों को मैच नहीं खेलने दिया जा रहा है। क्रिकेट खिलाड़ी आशुतोष प्रजापति ने सरगुजा क्रिकेट संघ के विनीत विशाल जायसवाल पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सुबह स्टेडियम में मैच खेलने के लिए बच्चे और दूसरे खिलाड़ी पहुंचे थे, लेकिन कुछ देर बाद एसोसिएशन के सेक्रेटरी पहुंचे और कहा कि यहां कोई मैच नहीं होगा।खिलाड़ियों को उन्होंने खेलने से मना कर दिया। क्रिकेट खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि संघ के सचिव को क्रिकेट पसंद नहीं है, इसी वजह से यहां कोई मैच भी नहीं होता है। बच्चों को यहां कभी खेलने नहीं दिया जाता है। बच्चों को स्टंप भी नहीं दिए जा रहे हैं। ग्राउंड में ताला मार दिया जाता है। अंडर 14 खेलने वाले खिलाड़ी के पिता पीयूष त्रिपाठी कहते हैं कि सुबह अंडर 14 का मैच था। एक टूर्नामेंट हो रहा था।

पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतार, लिमिट में मिल रहा फ्यूल

बलरामपुर। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी है। कई पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम होने से वाहन चालकों को सीमित मात्रा में ईंधन दिया जा रहा है। दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए लिमिट तय कर दिया है। लोडिंग कम आने से कई पेट्रोल पंप ड्राई होने की कगार पर हैं। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की वजह से लोगों की जेब पर महंगाई की मार भी पड़ने लगी है। बलरामपुर जिले में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत से लोगों को पंपों पर लिमिट में फ्यूल दिया जा रहा है इसकी वजह ज्यादातर पेट्रोल पंप पर फ्यूल स्टॉक की कमी बताया जा रहा है। रामानुजगंज के पुलिस पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाने पहुंची अमिता गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां दो सौ रूपये से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे हैं पेट्रोल का रेट भी तीन रूपये बढ़ा दिया गया है। बहुत समस्या हो रहा है डेली आने जाने में बहुत दिक्कत होगा। उपर से ही लोड कम आ रहा है इसलिए हर वाहन में लिमिट कर दिया गया है।

महानदी का सीना चीरने वाले खनन माफियाओं पर शिकंजा

नाकेबंदी में 14 ओवरलोड हाइवा जब्त

आरंग। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी का सीना चीरकर अवैध कमाई में जुटे रेत माफियाओं के खिलाफ रायपुर खनिज विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। रायपुर कलेक्टर के सख्त आदेश और खनिज प्रशासन के उप संचालक राजेश मालवे के कड़े तेवरों के बाद विभाग ने आरंग-खरोरा मुख्य मार्ग पर ग्राम रानीसागर में आधी रात को बड़ी नाकेबंदी की। इस हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन में अवैध रेत से लदे 14 भारी-भरकम हाइवा वाहनों की जब्ती की गई। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक, खनिज विभाग को पिछले कुछ समय से रंग क्षेत्र से रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर रेत तस्करी के लगातार इनपुट्स मिल रहे थे। सूचना की तस्दीक होते ही खनिज निरीक्षकों की टीम ने ग्राम रानीसागर के पास नाकेबंदी की। जैसे ही रेत से भरे हाइवा वाहनों का काफिला वहां से गुजरा, टीम ने उन्हें रोक लिया। जब चालकों से वैध दस्तावेज, रॉयल्टी रसीद और पीटपास (परिवहन पास) की मांग की गई, तो वे सकपका गए। बिना किसी वैध कागजात के शासकीय संपदा की चोरी कर जा रहे इन सभी 14 हाइवा वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया गया। सभी वाहनों को खरोरा थाना परिसर में सुपुर्द कर दिया गया है। इन सभी वाहन स्वामियों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं है। पिछले 15 दिनों से खनिज विभाग चौबीसों घंटे एक्शन मोड में काम कर रहा है। विभाग ने रेत के इस काले कारोबार पर तीनतरफा वार किया है, जिसमें नदी के प्रतिबंधित क्षेत्रों में मशीनों की एंट्री रोकने, मुख्य और चोर रास्तों पर अचानक जांच करने और गांवों के पास बिना अनुमति जमा की गई लाखों रुपए की रेत की जांच करने जैसी कार्रवाई असरदार साबित हो रही है। इस बैक-टू-बैक एक्शन ने माफियाओं के पूरे सिंडिकेट और उनकी आर्थिक रीढ़ को तोड़कर रख दिया है। रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने आरंग क्षेत्र में महानदी की प्राकृतिक संरचना को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अंधाधुंध और बेतरतीब ढंग से की गई खुदाई के कारण नदी ने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया है। नदी के गहरे होने से तटीय गांवों का वाटर लेवल (भूजल स्तर) तेजी से गिर रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि भारी वाहनों के कारण सड़कें बर्बाद हो रही थीं और धूल का गुबार उड़ रहा था। प्रशासन की इस कड़क कार्रवाई के बाद अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। रेत माफियाओं के रसूख और टकराव की आशंका को देखते हुए इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय और मुस्तैदी से अंजाम दिया गया। इस साहसिक कार्रवाई में खनिज विभाग की पूरी टीम ने रात भर मोर्चा संभाला, जिसमें मुख्य रूप से खनिज निरीक्षक प्रवीण नेताम और प्रीति सिन्हा, सुपरवाइजर सुनील दत्त शर्मा, राजू बर्मन (सैनिक) अन्य शामिल रहे।

गायत्री परियोजना प्रभावितों के लिए बड़ी सौगात, जोबगा में 95 रोजगार का रास्ता साफ

सूरजपुर। जिले के तहसील सूरजपुर अंतर्गत केतका स्थित गायत्री भूमिगत परियोजना, विश्रामपुर एसईसीएल क्षेत्र के लिए जिला पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना से प्रभावित भूमिस्वामियों एवं आश्रितों के पुनर्वास और रोजगार संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान ग्राम जोबगा की अधिग्रहित निजी भूमि से संबंधित भूमिस्वामियों एवं आश्रितों को कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। प्रभावित परिवारों को नीति के तहत निर्धारित रोजगार के दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करने के लिए बैठक आयोजित की गई। जिसमें घटते क्रम में वरीयता सूची के विकल्प पर सहमति व्यक्त की गई । बैठक में लिए गए इस निर्णयों के आधार पर ही अब प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया कि गायत्री भूमिगत परियोजना के अंतर्गत कुल 288.209 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसमें 220.784 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है। परियोजना से ग्राम जोबगा, गेतरा और पोड़ी प्रभावित हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम जोबगा में कुल 77.69 हेक्टेयर (191.976 एकड़) भूमि अधिग्रहित की गई है। मुआवजा निर्धारण के समय यहां 168 खातेदार थे, जबकि अधिग्रहण तिथि के समय इनकी संख्या 161 खातेदार रही। निजी भूमि के लिए कुल 20.17 करोड़ रुपए मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। इसमें अब तक 42 खातेदारों को 7.09 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 126 खातेदारों को 13.08 करोड़ रुपए का भुगतान शेष है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 के तहत परियोजना प्रभावितों के लिए 95 रोजगार का प्रावधान किया गया है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका ने कवर्धा कलेक्ट्रेट परिसर में रोपा आम का पौधा

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कबीरधाम

प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर कवर्धा में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधरोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की अपील की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने भी पौधरोपण किया। राज्यपाल डेका ने कहा कि पेड़-पौधे पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पौधरोपण केवल वर्तमान के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम में कलेक्टर गोपाल वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह, वनमण्डलाधिकारी श्री निखिल अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे कोसला धाम

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत शनिवार को जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड स्थित ग्राम कोसला पहुंचकर माता कौशल्या मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने माता कौशल्या एवं प्रभु श्रीराम से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और छत्तीसगढ़ की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री साय के मंदिर परिसर पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंदिर सेवा समिति एवं ग्रामीणों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी भी उनके साथ उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं एवं ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आस्था और परंपराएं प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। हमारी सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। मंदिर सेवा समिति द्वारा मुख्यमंत्री श्री साय को माता कौशल्या मंदिर का आकर्षक छायाचित्र स्मृति स्वरूप भेंट किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय के अचानक आगमन से क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का वातावरण देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, ग्रामीणजन एवं स्थानीय नागरिक इस अवसर पर उपस्थित थे।

भाटापारा स्टेशन पर टिकट चेकिंग, 342 मामलों से 207720 रुपए राजस्व की प्राप्ति

रायपुर। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी के निर्देश पर रायपुर मंडल में भाटापारा रेलवे स्टेशन पर किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान दिनांक 14 मई, 2026 को चलाया गया। जिसमें भाटापारा रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म, ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले लगभग 193 यात्री पकड़े गए, जिससे 1,56,025 राजस्व प्राप्त हुआ। अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले 91 यात्रियों से 48, 895 रूपये राजस्व प्राप्त हुआ, अधिक लगेज लेकर यात्रा करने वाले 21 यात्रियों से 2100 रूपये राजस्व प्राप्त हुआ और रेलवे स्टेशन पर कचरा फैलाने वाले 37 यात्रियों से 3700 रूपये राजस्व प्राप्त हुआ जो इस किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान में कुल 342 मामलों को दर्ज कर 2,07, 720 रुपए राजस्व प्राप्त किया गया। इस टिकट चेकिंग का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को टिकट लेने के प्रति जागरूक करना था। इस टिकट चेकिंग अभियान का संचालन सहायक वाणिज्य प्रबंधक अविनाश कुमार आनंद के द्वारा एवं 1 मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, 1 वाणिज्य निरीक्षक, 16 टिकट चेकिंग स्टाफ, 2 आरपीएफ स्टाफ शामिल रहे । रेल प्रशासन यात्रियों को आगाह किया है कि वे यात्रा हेतु उचित टिकट एवं रेल परिसर मे प्रवेश करने के पहले प्लेटफॉर्म टिकट अवश्य खरीदें। रेलगाड़ी एवं रेल परिसर को साफ सुथरा रखने में भी रेल प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर देश में भव्य वॉकथन का हुआ आयोजन

रायपुर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केन्द्र द्वारा भव्य वॉकथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आकाशवाणी के वर्तमान कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी, समाचार वाचक, श्रोता, युवा वर्ग तथा शहर के अनेक प्रमुख नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा, समाज में उसके योगदान तथा जनसंचार के क्षेत्र में उसकी विश्वसनीय भूमिका को स्मरण करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जायभाये तथा माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों और युवाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही।

जल संरक्षण जन आंदोलन बने, तभी बढ़ेगा भूजल : राज्यपाल

■ कबीरधाम जिले में विकास कार्यों के संबंध में बैठक

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कबीरधाम जिले में विकास कार्यों के संबंध में बैठक लेकर वर्षा जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को व्यापक स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जन अभियान का रूप देना आवश्यक है, तभी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को भूजल संकट से बचाया जा सकेगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा भी उपस्थित रहीं।

राज्यपाल डेका ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिलास्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि वर्षा जल प्रकृति का मुफ्त संसाधन है, जिसे सहेजकर न केवल वर्तमान जरूरतें पूरी की जा सकती हैं बल्कि भूजल स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक पक्के भवन और प्रधानमंत्री आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर जोर दिया। साथ ही खेतों में डबरी निर्माण कर वर्षा

जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने तथा प्रारंभिक स्तर पर बड़े किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने की बात कही।

राज्यपाल डेका ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल पौधरोपण ही नहीं बल्कि उनका संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है, जिससे जिले का फॉरेस्ट कवर बढ़ सके। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को अपनाने, किसानों को प्रशिक्षण देने, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा हाइड्रोपोनिक्स और ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक कृषि पद्धतियों पर बड़े स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता बताई।

पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते हुए राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि योजना का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार लाना है। उन्होंने आवास, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए योजना के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने टीबी मरीजों के उपचार, पोषण आहार उपलब्धता तथा मल्टीपल टीबी मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर कर समुचित उपचार सुनिश्चित करने पर बल दिया। महिलाओं में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नियमित स्क्रीनिंग कैंप आयोजित करने के भी निर्देश दिए। राज्यपाल ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा एम्स के साथ एमओयू किया गया है, जिसके तहत मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने रेड क्रॉस वार्षिक सदस्यता अभियान को बढ़ाने पर भी जोर दिया और कहा कि लोगों की छोटी-छोटी मदद किसी का जीवन बदल सकती है।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि हर जिले और विकासखंड की अपनी अलग पहचान होनी चाहिए, जो योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों से अपने कार्यक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लोगों के जनजीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने की बात कही। बैठक में कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा , पुलिस अधीक्षक सहित सभी एसडीएम व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

देश जब संकट में होता है, पीएम नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं: कांग्रेस

रायपुर। महंगाई और पीएम के विदेश दौरों को लेकर एक बार कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शनिवार को जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने महंगाई और वैश्विक समस्या को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की। मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री ने कहा कि देश वर्तमान समय में वैश्विक संकट से गुजर रहा है। जिसमें एलपीजी पेट्रोल डीजल की कमी पूरे देश में महसूस की जा रही है।

पूर्व मंत्री ने कहा कि देश में जब इस तरह की समस्या है, ऐसे में पीएम मोदी का विदेश दौरा होना कई सवालों को जन्म देता है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम कह रहे हैं कि 1 साल तक लोग सोना नहीं खरीदें। कांग्रेस ने कहा कि हमारे यहां शादी विवाह में बेटी या बहू को मंगलसूत्र दिया जाता है। ऐसे में पीएम अपील बेटे-बहू के गले से मंगलसूत्र छीनने वाली लगती है।

शिव डहरिया ने कहा जब जब देश में संकट आता है। नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं, देश की समस्याओं का

निराकरण नहीं करते। देश में जब संकट आता है तो सिर्फ उपदेश देने का काम पीएम करते हैं। वर्तमान समय में पूरे देश में पेट्रोल डीजल का संकट है। किसानों को खाद और बीज नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। ऐसी स्थिति विश्व के दूसरे देशों में नहीं है। इस तरह की स्थिति केवल भारत में देखने को मिल रही है। भारत में इस तरह की स्थिति इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार देश में फेल है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं।

प्रेस कांफ्रेस के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जनता के हित की बात करते हैं। डहरिया ने कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व में ही पीएम मोदी को आने खतरे से आगाह किया था। लेकिन पीएम मोदी कभी भी हमारे नेता राहुल गांधी की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कांग्रेस ने कहा कि आज उसी का नतीजा है कि देश कई बड़ी सस्याओं से जूझ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि आने वाले दिनों में परेशान जनता भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सबक सिखाएगी। डहरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महंगाई और आम जनता की तकलीफ को सड़क पर उठाती रहेगी।

शहर की स्वच्छता से कोई समझौता नहीं संवाद के द्वार हमेशा खुले हैं: महापौर

■ काम करने वालों को रोकना कानूनन गलत, स्वच्छता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

रायपुर। रायपुर की स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और रामकी कंपनी के कुछ ड्राइवरों द्वारा काम बंद किए जाने के विषय पर महापौर ने अपना स्पष्ट रुख साझा किया है। महापौर ने कहा है कि सफाई कर्मचारी और ड्राइवर शहर की व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में शहर की जनता को गंदगी और अव्यवस्था के बीच नहीं छोड़ा जा सकता।

महापौर ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ कर्मचारी न केवल स्वयं काम बंद कर रहे हैं, बल्कि उन ड्राइवरों को भी काम करने से रोक रहे हैं जो अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं। महापौर ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन काम करने के इच्छुक कर्मचारियों को रोकना या उन्हें डराना नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। काम रोकना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

शहर की सफाई व्यवस्था पर जोर देते हुए महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रायपुर की स्वच्छता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया

जाएगा। उन्होंने रामकी कंपनी के प्रबंधन को निर्देशित किया है कि वे वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि वार्डों से कचरा उठाने का काम प्रभावित न हो। उन्होंने प्रशासन को भी स्थिति पर नजर रखने और काम में बाधा डालने वाले तत्वों पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।

महापौर ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे द्वार हर नागरिक और कर्मचारी के लिए हमेशा खुले हैं। यदि किसी की कोई समस्या है, तो वे चर्चा कर सकते हैं। संवादहीनता और काम का बहिष्कार शहर के हितों के खिलाफ है। मैं ड्राइवरों से अपील करती हूँ कि वे शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और तुरंत काम पर लौटें। महापौर ने अंत में दोहराया कि प्रशासन कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन शहर की सफाई और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वे कड़े निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटेंगी।

जनदर्शन में कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने सुनीं आम जनता की समस्या

अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश

रायपुर। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने लखनपुर स्थित अपने निज निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में बड़ी

संख्या में पहुंचे ग्रामीणों, महिलाओं और नागरिकों ने सड़क, बिजली, पेयजल, राजस्व प्रकरण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। मंत्री अग्रवाल ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा हर शिकायत का निराकरण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना चाहिए। जनदर्शन के दौरान मंत्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता और विकास को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। शासन की मंशा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी पात्र हितग्राही को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में अधोसंरचना विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश देते हुए कहा कि फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और जनता की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है और इस विश्वास को बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

शाह के प्रस्तावित बस्तर प्रवास की तैयारियों का उप मुख्यमंत्री शर्मा ने लिया जायजा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित बस्तर प्रवास को लेकर तैयारियों का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर से कार्यक्रम स्थल

को जाने के लिए निजी वाहन के स्थान पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुरूप सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ पूल वाहन के रूप में बस से सफर किया। जगदलपुर विकासखंड के नेतानार स्थित शहीद गुण्डाधुर सेवा डेरा पहुंचकर उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सेवा डेरा परिसर में संचालित सेवा सेतु केंद्र, बैंक सखी केंद्र तथा महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित आर्थिक गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके कार्यों की जानकारी ली तथा स्वरोजगार और आजीविका संवर्धन के प्रयासों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में बेहतर कार्य कर रही हैं। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सेवा सेतु केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा स्थल का भी निरीक्षण किया तथा वहां साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, रंग-रोगन और आवश्यक सजावट सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर के महान जननायक शहीद गुंडाधुर की स्मृति से जुड़ा यह स्थल गौरव का प्रतीक है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं बेहतर और सुव्यवस्थित होनी चाहिए।

इस अवसर सांसद महेश कश्यप, अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि, प्रमुख सचिव निहारिका बारीक, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास भीम सिंह, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय, सीईओ जिला पंचायत प्रतीक जैन एवं जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन तथा संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

पक्के घर का सपना हुआ साकार

मुख्यमंत्री ने लेमरू में हितग्राही धरम सिंह के नए आवास में कराया गृह प्रवेश

रायपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कोरबा जिले के लेमरू पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही श्री धरम सिंह के नव निर्मित आवास का उद्घाटन एवं गृह

प्रवेश कराया। वर्षों तक कच्चे मकान में कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने वाले धरम सिंह के परिवार के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और नए घर के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आवास का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और नई उम्मीद लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आगे बढने् के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर पैनल स्थापना हेतु डीएमएफ मद से हितग्राही अंशदान की 60 हजार रुपये की राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को केवल आवास ही नहीं, बल्कि बेहतर जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री के आगमन से धरम सिंह का परिवार भावुक हो उठा। परिवार ने आत्मीय स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से मिले लाभों के लिए आभार व्यक्त किया। पूरे गांव में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने कहा कि अब योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है और लोगों का शासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। इस अवसर पर उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

अरुण देव गौतम बने पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक

■ अब तक कार्यवाहक के तौर पर कर रहे थे काम

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार राज्य के लिए पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के नाम की घोषणा कर दी। 16 मई को छत्तीसगढ़ के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में, 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण देव गौतम को पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। इससे पहले अरुण देव गौतम प्रभारी पुलिस महानिदेशक के तौर पर छत्तीसगढ़ का काम-काज देख रहे थे।

छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण

देव गौतम बनाए गए हैं जो पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक होंगे। हालांकि अरुण देव गौतम ही छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक का काम देख रहे हैं, लेकिन वह पूर्णकालिक डीजीपी के तौर पर नहीं नियुक्त किए गए थे। अरुण देव गौतम पिछले 14 महीने से छत्तीसगढ़ के प्रभारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर काम देख रहे थे और उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी कौन होगा, इसकी चर्चा भी खूब हो रही थी। इस बात को लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काफी किरकिरी भी होती थी। आलोचना में ये कहा जाता था कि सरकार एक पूर्ण कई पुलिस महानिदेशक नहीं दे पा रही है। हालांकि सरकार ने अब अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का पुलिस प्रमुख बना दिया है।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 03.06.2026, (17.30 बजे) तक ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है:-

सिस्टम निविदा क्रमांक	निविदा सूचना क्रमांक एवं दिनांक	कार्य का नाम	निविदा की लागत जी.एस.टी. छोड़ कर (लाख में)	आमंत्रण का क्रमांक
190801	01/व.ले.लि / 2026-27 दिनांक 13.05.2026	रजपुरी व्यपवर्तन योजना का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य।	877.82	प्रथम आमंत्रण

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 20.05.2026, समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड़ किये जा सकते है।

नोट -1. निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

2. निविदा की अनुमानित लागत एस.ओ.आर. दिनांक 01.05.2025 एवं दिनांक 08.08.2025 के जारी संशोधन के अनुसार है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, जशपुर (छ.ग.)
कृते मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर, (छ.ग.)

जी-262700741/8

केरल से कांग्रेस आलाकमान का संदेश

दिलीप कुमार पाठक

केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की बंपर जीत के बाद कांग्रेस आलाकमान ने एक बहुत बड़ा और सकारात्मक राजनीतिक फैसला लिया है। दिल्ली दरबार ने किसी भी गुटबाजी के आगे न झुकते हुए केरल के लोकप्रिय नेता वी. डी. सतीशन को नया मुख्यमंत्री चुनकर देश भर के कार्यकर्ताओं को एक ठोस संदेश दिया है। यह संदेश जनता की तरफ से नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस नेतृत्व की ओर से आया है, जिसने यह जता दिया है कि अब पार्टी पुराने ढर्रे और गलतियों से सबक सीख चुकी है। आलाकमान का यह कदम साफ इशारा करता है कि संगठन को मजबूत करने के लिए अब केवल जमीन पर पसीना बहाने वाले चेहरों को ही तवज्जो दी जाएगी।कांग्रेस के इतिहास में लंबे समय से एक बड़ी कमजोरी रही है, जहां जमीन पर रात-दिन काम करने वाले जनप्रिय नेताओं की जगह दिल्ली में लॉबिंग करने वाले नेताओं को कमान सौंप दी जाती थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में जनता और कार्यकर्ता दिल से चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे ऊर्जावान युवाओं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन दिल्ली दरबार ने पुराने समीकरणों को प्राथमिकता देते हुए कमलनाथ और अशोक गहलोत के हाथों में सत्ता सौंप दी। नतीजा यह हुआ कि संगठन कमजोर होता गया और अंदरूनी कलह से राज्यों में बनी-बनाई सरकारें हाथ से निकल गईं या कमजोर हो गईं। केरल के ताजा फैसले से कार्यकर्ताओं में यह बड़ी उम्मीद जगी है कि आलाकमान अब बहुत जल्द कर्नाटक और हरियाणा की इस आपसी लड़ाई को भी इसी कड़े नेतृत्व के साथ हमेशा के लिए दूर करेगा। पार्टी के शीर्ष नेताओं को अब बिना वक्त गंवाए इन दोनों राज्यों के मतभेदों को सुलझाना चाहिए ताकि वहां भी संगठन को एकजुट और मजबूत किया जा सके। केरल में लिया गया यह फैसला पूरी पार्टी के लिए एक बेहतरीन नजीर बन गया है। वी. डी. सतीशन पिछले पांच सालों से विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में लगातार सरकार को घेर रहे थे और कार्यकर्ताओं के सुख-दुख में साथ खड़े थे। आलाकमान ने जमीनी हकीकत को सर्वोपरि मानकर उनके नाम पर मुहर लगाई। इससे पैराशूट नेताओं का दौर खत्म हुआ है और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह जागा है। उन्हें यह भरोसा मिला है कि अब दिल्ली की पैरवी नहीं, बल्कि जमीन पर किया गया काम ही नेता तय करेगा। इस निर्णय के साथ ही विपक्ष का वह एजेंडा भी पूरी तरह हवा में उड़ गया, जिसमें दुष्प्रचार किया जा रहा था कि होने वाले मुख्यमंत्री इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पसंदीदा हैं और कांग्रेस तुष्टिकरण के रास्ते पर चल रही है। सतीशन की धर्मनिरपेक्ष और बेदाग छवि ने इस पूरे राजनीतिक एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। क्यों कि मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने से ठीक पहले, वी. डी. सतीशन ने तिरुवनंतपुरम के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूरी विधि-विधान से पूजा-पाठ की और उनका आशीर्वाद लिया। पारंपरिक सफेद मुंडू और शॉल में उनकी मंदिर की ये तस्वीरें यह साफ करती हैं कि वे जनता की सांस्कृतिक आस्थाओं का कितना गहराई से सम्मान करते हैं और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। कुल मिलाकर, केरल के बहाने कांग्रेस आलाकमान ने खुद को बदलने और सुधारने का एक बड़ा संदेश दिया है। अब पार्टी को बिना समय गंवाए कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों में चल रहे पुराने मकड़जाल को भी पूरी तरह साफ करना होगा। जब तक दिल्ली से थोपे जाने वाले फैसलों को बंद करके जमीनी संघर्ष करने वालों को हक नहीं मिलेगा, तब तक पूरे देश में संगठन मजबूत नहीं हो सकता।

हिंदुत्व मॉडल के जरिये बंगाल में बड़े बदलाव

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता की कमान संभालते ही चुनावी वादों पर अमल की दिशा में कदम बढ़ाने तो शुरू कर ही दिये हैं साथ ही राज्य की राजनीति और प्रशासन में तेज बदलावों का दौर भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्हें राज्य की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को उनके गढ़ में पराजित कर सत्ता तक पहुंचे सुवेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के केवल 48 घंटे के भीतर लगभग डेढ़ दर्जन बड़े निर्णयों की घोषणा कर यह संकेत दे दिया कि नई सरकार प्रशासनिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर व्यापक बदलाव चाहती है।

नई सरकार के शुरुआती फैसलों में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सख्ती प्रमुख रही। सरकार ने स्पष्ट किया कि सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी तथा धार्मिक गतिविधियां निर्धारित परिसरों तक सीमित रहेंगी। कोलकाता के रेड रोड क्षेत्र में सार्वजनिक नमाज पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी नियंत्रण लगाया गया है। सरकार ने पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

साथ ही सुवेंदु अधिकारी सरकार ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2023 के पंचायत चुनावों के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। इन मामलों को पिछली सरकार के दौरान बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित और बंद मामलों की दोबारा जांच कराने का निर्देश दिया। सरकार का कहना है कि चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है।

इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामलों को भी दोबारा जांच के दायरे में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पंद्रह वर्षों में मारे गए तीन सौ इक्कीस भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार यदि चाहें तो सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी। यह फैसला राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर भाजपा के लंबे अभियान का

हिस्सा माना जा रहा है।

इसके अलावा, नई सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई करने और पुलिस को बिना राजनीतिक दबाव के काम करने की खुली छूट देने की घोषणा की है। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और किसी की राजनीतिक पहचान को महत्व न दिया जाए। सरकार ने दावा किया है कि कानून व्यवस्था को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त किया जाएगा।

साथ ही सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और पशु तस्करी के मुद्दे पर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य में अवैध पशु बाजारों को बंद करने और अवैध परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर चौबीस परगना जिलों में चल रहे अवैध पशु बाजारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को पैंतालीस दिनों के भीतर भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अवैध घुसपैठ और जनसंख्या संतुलन में हो रहे बदलावों पर रोक लगेगी।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य में पशु वध को लेकर भी सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब किसी भी पशु के वध से पहले उसकी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र नगर निकाय प्रमुख और सरकारी पशु चिकित्सक की संयुक्त सहमति से जारी किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और केवल निर्धारित बूचड़खानों में ही इसकी अनुमति होगी। नियमों के उल्लंघन पर छह महीने तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। नई सरकार के इस कदम को कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साथ ही राज्य में लंबे समय से चर्चा में रहे सिंडिकेट राज और अवैध खनन पर भी सरकार ने कार्रवाई का संकेत दिया है। जिला और प्रखंड स्तर पर सक्रिय कथित सिंडिकेट नेटवर्क को समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि पिछली व्यवस्था में निर्माण सामग्री और कई क्षेत्रों में प्रभावशाली समूहों का नियंत्रण था, जिसे खत्म करना आवश्यक है।

सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव करते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की सुरक्षा हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस शासनकाल में विभिन्न बोर्डों, सार्वजनिक उपक्रमों और गैर वैधानिक संस्थाओं में नियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। साठ वर्ष से अधिक आयु वाले अधिकारियों को सेवा विस्तार देने पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

नई सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना, विश्वकर्मा योजना और उज्ज्वला योजना को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समझौते तेजी से पूरा करने को कहा है।

साथ ही राज्य की नई भाजपा सरकार ने शिक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े मोर्चे पर भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार कक्षाएं शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को वंदे मातरम् के छहों पद गाने होंगे।

इसके अलावा, कानूनी ढांचे में बदलाव करते हुए भारतीय न्याय संहिता को राज्य में लागू करने की घोषणा भी की गई है। यह नया आपराधिक कानून पुराने भारतीय दंड संहिता का स्थान ले चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका कार्यान्वयन लंबित था। नई सरकार ने इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है।

सरकारी नौकरियों के इच्छुक युवाओं को राहत देते हुए आयु सीमा चालीस से बढ़ाकर पैंतालीस वर्ष कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय से अवसरों से वंचित युवाओं को लाभ मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

जनगणना प्रक्रिया को भी नई सरकार ने फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद यह प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब बिना किसी राजनीतिक अहंकार के केंद्र के निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगी।

इसके अलावा, प्रशासनिक ढांचे में सुधार की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने का फैसला किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर के मानकों से जोड़ना है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के आठ अधिकारियों ने नई दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। शहरी विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इसे पश्चिम बंगाल की नौकरशाही में बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत माना जा रहा है।

बहरहाल, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही हिंदुत्व आधारित राजनीति को जमीन पर उतारने की दिशा में तेज कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पर सख्ती, वंदे मातरम् को अनिवार्य करना, सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जैसे फैसलों को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा लंबे समय से बंगाल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाती रही है और अब सरकार बनने के बाद उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि राज्य की एक बड़ी आबादी भी लंबे समय से ऐसे बदलावों की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसका असर चुनाव परिणामों में भी देखने को मिला। नई सरकार के शुरुआती फैसलों ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक दिशा दोनों में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इस तरह कुछ समय तक स्त्री जीवन बिताते हुवे मनुपुत्र सुद्युम्न ने अपने कुलपुरोहित वसिष्ठ जी को स्मरण किया- ऐसा सुना जाता है ॥36॥ वसिष्ठ जी (समाधि द्वारा) सुद्युम्न की दुर्दशा देखकर अतीव दु:खित हुये तथा फिर से उसको पुरुष बनाने के लिये श्री शङ्कर भगवान् के पास पहुंचे।।37।। सो शिवजी ने प्रसन्न होकर वसिष्ठ की अभिलाषा पूर्ण करने के लिये [कहा कि]॥ 38।। आपका गोत्रज सुद्युम्न एक मास पुरुष और एक मास स्त्री रहा करेगा॥ 36।।

समाधान

उपर्युक्त आख्यान को पढ़कर जो महाशय शङ्कापङ्क निमग्न हो जाते हैं उन्हें न केवल प्रकृति-वैलक्षण्य से ही बल्कि सामयिक घटनाओं से भी सर्वथा अपरिचित समझना चाहिए, क्योंकि उन्हें यह विदित नहीं कि भला! इस कथा में तो जिस यज्ञ द्वारा सन्तानोत्पादन किया जा रहा था उसमें रानी के कहने से होता ने कन्योत्पादक मन्त्रों को पढ़कर तादृश मन्त्रशक्ति के बल से भविष्य में कन्या सन्तति के उत्पादन की योग्यता का आधान कर दिया था अत: वसिष्ठ जी के तपोबल से ही वह कन्या पुंस्त्व को प्राप्त हो सकी थीं, और फिर जगन्नियन्ता श्री महादेव जी के प्रताप से हिमालय के खास प्रदेश में तादृश वातावरण के तारतम्य से स्त्रीभावापन्न हो गई थी, तथा पश्चात् कर्तुमकतु मन्यथाकतु प्रभुः महेश्वर के अनुग्रह से ही एक एक महीने बारी बारी से स्त्री पुरुष बनकर जीवन बिताने का वर मिला था- ऐसा लिखा है जो मन्त्र-शक्ति तपोबल एवं देव-सामर्थ्य रूप कारणों का मनन करने से प्रत्येक आस्तिक के हृदय को समाहित कर सकता है, परन्तु हम तो आज के समय में भी यदृच्छा ही इस प्रकार की घटनाओं का घटना देखते हैं : अर्थात् अब भी गत वर्षों में कई स्त्रियों का पुरुष बन जाना और पुरुषों का स्त्री बन जाना समाचारपत्रों में पढ़ चुके हैं। **क्रमशः ...**

विश्व दूरसंचार दिवस

विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन हमें दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व की याद दिलाता है और दुनिया भर में सशक्त डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दूरसंचार ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। चाहे वह इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट संचार या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हों, ये सभी तकनीकें आज के युग में हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं। डिजिटल युग में संचार केवल संदेश भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं और वैश्विक सहयोग का आधार भी बन गया है।

17 मई, 1865 को पेरिस में पहले अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई।

यह संगठन दुनिया भर में संचार नेटवर्क और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में 1969 से यह दिवस मनाया जा रहा है।

जागरूकता फैलाना- इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोगों को यह बताना है कि सूचना और संचार तकनीक और इंटरनेट हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकते हैं।

डिजिटल अंतर को कम करना- दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी इंटरनेट और तकनीक की पहुंच नहीं है। यह दिन सरकारों और संगठनों को इस डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए प्रेरित करता है।

महत्व- यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कनेक्टिविटी ने टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। जिसके उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना। विकासशील और कम विकसित देशों को तकनीक के जरिए सशक्त बनाना, आर्थिक उन्नति करना, ताकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिला सकें।

नाम परिवर्तन- साल 2006 तक इसे केवल विश्व दूरसंचार दिवस कहा जाता था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसमें सूचना समाज दिवस को भी जोड़ दिया, जिससे अब इसे विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में जाना जाता है।

वर्ष 2026 में विश्व दूरसंचार दिवस 2026 की थीम- डिजिटल जीवन रेखाएं : एक संयोजित दुनिया में लचीलेपन को मजबूत करना तय की गई है। जिसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है।

अत: 17 मई को पूरी दुनिया इस दिवस को मनाएगी। हर साल इसकी एक विशेष थीम रखी जाती है, जो वर्तमान वैश्विक चुनौतियों- जैसे एआई, साइबर सुरक्षा या ग्रामीण कनेक्टिविटी पर आधारित होती है। विश्व दूरसंचार दिवस का आयोजन अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा किया जाता है।

चीन के धुन पर नाचने पर अचानक क्यों मजबूर हुआ अमेरिका?

अभिनय आकाश

अमेरिका और चीन के शीर्ष नेताओं- डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने एक-दूसरे से अच्छे रिश्ते पर जोर दिया है और जमकर एक-दूसरे की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शुरुआती संबोधन में शी जिनपिंग को महान नेता बताया है। वहीं चीनी राष्ट्रपति ने दोस्ती पर जोर देते हुए दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। बीजिंग की फ्लाइट में बैठने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दोस्त जिनपिंग से मिलूंगा तो ईरान पर लंबी बातचीत करूंगा। ऐसी ख्वाहिश जाहिर करने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ही कहा था कि ईरान पर चीन से कोई खैरात नहीं चाहिए, हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उनमें ईरान नहीं होगा। ईरान की बात ही क्या करनी। वो तो तो हमारे कंट्रोल में है और नेस्तोनाबूद है। जो ईरान ट्रंप के बयानों में नेस्तोनाबूद है वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की फाइलों नें चुपचाप अपनी ताकत समेट रहा है। तहखानों में मिसाइलें फिर से तैनात हो रही हैं। लॉन्चर्स अपनी जगह पर लौट आए हैं। खबर है कि डीलमेकर-पीसमेकर दो दिन पहले फिर से बड़े हमले का मन बना रहे थे। फिर बीजिंग के लिए निकल लिए। इतना लंबा नैरेशन देने के पीछे का मकसद ये है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं इन सब से जंग के भविष्य का पता नहीं चलता। फिर भी दुनिया शांति के सपने देख रही है। जैसे मानो दो सुपरपावर मिल रहे है तो गैस, पेट्रोल और डीजल तो सस्ते हो ही जाएंगे। भले ही वो दोनों सुपरपावर बंद कमरों में अपने मतलब की चीज खरीदने-बेचने के सौदे निपटा रहे हो। आज इन्हीं अनिश्चितताओं का एमआरआई स्कैन करेंगे। ये भी बताएंगे कि इस मुलाकात का भारत अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा।

अमेरिका का पूरा ध्यान अंग्रेजी के 'बी' अक्षर से शुरू होने वाले पांच मोर्चों पर टिका है- बोइंग विमान, बीफ, बीन्स यानी सोयाबीन, बोर्ड ऑफ ट्रेड (व्यापार बोर्ड) और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (निवेश बोर्ड)। अमेरिका की मंशा बिल्कुल साफ है। वह

सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी संवेदनशील और अहम तकनीकों को विवादों से बचाकर रखना चाहता है, जबकि बाकी सामान्य व्यापार को पटरी पर लाना चाहता है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि चीन के मौजूदा आर्थिक ढांचे से निपटने के लिए पुराने नियम अब नाकाफी हैं, इसलिए वे अब सीधे और बराबरी के सौदों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, चीन का सारा जोर 'टी' अक्षर वाले तीन मुख्य मुद्दों पर है- ताइवान, टैरिफ यानी आयात शुल्क और टेक्नोलॉजी। चीन की कोशिश है कि अमेरिका द्वारा उस पर लगाए गए तकनीकी और निवेश प्रतिबंधों में ढील दी जाए और दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनातनी पर लंबे समय के लिए विराम लगे। दरअसल, अमेरिका की सख्त पाबंदियों ने चीन को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से धकेल दिया है। इस वक्त चीन की आर्थिक रफ्तार भी कुछ धीमी पड़ी है, जिससे वहां की सरकार पर बाहरी व्यापार को सुधारने का भारी दबाव है। ऐसे में, दुनिया भर में बदलते हालातों के बीच चीन की यह भी कोशिश है कि उसकी इलेक्ट्रिक कारों और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े अन्य उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों के दरवाज़े पूरी तरह से खुल जाएं।

यदि कभी व्यापार और शुल्क अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता की पहचान थे, तो अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत सेमीकंडक्टर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के मुख्य युद्धक्षेत्र बन गए हैं। शिखर सम्मेलन में तेजी से शक्तिशाली हो रहे अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों से उत्पन्न जोखिमों पर पहली बार गंभीर उच्च-स्तरीय चर्चा भी हो सकती है। यह उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जहां वाशिंगटन और बीजिंग बढ़ते अविश्वास के बावजूद सीमित सहयोग की आवश्यकता को समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधों में एक और बड़ी दरार बनकर उभरी है। एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस प्रीव्यू एक हाइटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली जो सॉफ्टवेयर कमजोरियों की स्वायत्त रूप से पहचान करने और जटिल साइबर ऑपरेशन करने में सक्षम है। इसके जारी होने से तेजी से शक्तिशाली हो रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंटों से उत्पन्न जोखिमों को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने एआई की सुरक्षा और दुरुपयोग पर संवाद स्थापित करने में सीमित तत्परता दिखाई है, फिर भी गहरा अविश्वास सहयोग पर हावी है। यह अविश्वास चीन के हालिया फैसले में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें उसने चीनी मूल की एआई स्टार्टअप कंपनी मैनस के मेटा द्वारा 2 अरब डॉलर के अधिग्रहण को रोक दिया, जो बीजिंग के अग्रणी एआई प्रतिभा और बौद्धिक संपदा को अपने रणनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर बनाए रखने के दृढ़ संकल्प का संकेत देता है। इस प्रकरण ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तकनीकी प्रतिस्पर्धा अब हार्डवेयर तक पहुंच से हटकर प्रतिभा, डेटा और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पर नियंत्रण की ओर बढ़ रही है। इन घटनाक्रमों से दोनों पक्षों के बीच शत्रुतापूर्ण धारणाएं और भी प्रबल होने की संभावना है, जिससे अंतर्निहित कबीले का प्रभाव और भी स्पष्ट हो जाएगा।

अपने पहले कार्यकाल में ही उन्होंने चीन से होने वाले आयात पर टैरिफ की घोषणा की थी। दूसरे टर्म में वह इस लड़ाई को और आगे ले गए और 125% तक टैरिफ जड़ दिया। हालांकि रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीनी नियंत्रण की वजह से आखिरकार ट्रंप को समझौता करना पड़ा था। टैरिफ वॉर भले थम गई हो, पर अमेरिका और चीन के बीच की होड़ कायम है। दोनों एक-दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, पर इतना नहीं जिससे बात ज्यादा बिगड़े। ईरान युद्ध के दौरान भी यह देखने को मिला है। ईरान की मदद के आरोप में अमेरिका ने कुछ चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि चीन ने वॉशिंगटन की नीतियों का विरोध किया, पर सब नियंत्रण में। इसकी वजह है आपसी निर्भरता और जरूरत। चीन के लिए अमेरिका आज भी सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि इस साल चीनी निर्यात में करीब 10त्न की कमी आई है। चीन की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए यह झटका है। खाड़ी देशों में भी उसका निर्यात घटा है। तेहरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार होने के नाते भी उसकी परेशानी बढ़ रही है। वह चाहता है कि युद्ध जल्दी थमे। दूसरी ओर, ट्रंप को ईरान पर समर्थन और निवेश के लिए चीन चाहिए। इसीलिए वह अपने साथ कई बड़े उद्यमियों को लेकर पहुंचे हैं।

भारत हाल के वर्षों में अमेरिका भारत का अहम रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। दूसरी ओर चीन भारत का अहम पड़ोसी देश है, जिसके साथ सीमा विवाद के बाद रिश्ते व्यवहारिक समझ पर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के आपसी संबंध और इस दौरे के निष्कर्ष भी भारत पर असर डालेगा। अमेरिका और चीन के रिश्ते एक लंबे वक्त तक असहजता के दायरे में रहे, जिसके जियोपॉलिटिकल प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा है। बीजिंग में चल रही बातचीत का तुरंत नतीजा चाहे जो हो। भारत के कूटनीतिक और विदेश नीति के विशेषज्ञ इन घटनाक्रमों पर पैनी नज़र है। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय तक चलने वाली इस गहरी खींचतान से, पहले से ही उलझी और बंटी हुई वैश्विक व्यवस्था पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे-जैसे दुनिया भर के व्यापार, तकनीक और कूटनीतिक रिश्ते दो अलग-अलग खेमों में बंटते जा रहे हैं, भारत की मल्टी-अलाइनमेंट (यानी किसी एक गुट में न बंधकर, सभी देशों के साथ संतुलन बनाकर चलने की) नीति की असली परीक्षा होगी।

आज का इतिहास

1884 अलास्का को एक अमेरिकी क्षेत्र में मिलाया गया।

1900 चीन में बॉक्सर्स द्वारा पेकिंग के 100 मील के भीतर तीन गांवों को जला दिया जिसमे 60 चीनी और क्रिश्चियन नागरिक मारे गए।

1902 एंटीकाइथेरा तंत्र, सबसे पुराना ज्ञात जीवित गियरडैमचैनिज्म है, जिसे एंटीकाइथेरा के ग्रीक द्वीप के एक जहाज से उतरने वाली कलाकृतियों के बीच खोजा गया था।

1909 प्रथम गिरो डी टालिया साइकिल दौड़ मिलान शहर में शुरू हुई, जिसमें लुइगी गन्ना विजेता हुए।

1914 अल्बानिया ने आधिकारिक तौर पर उत्तरी एपिरस के क्षेत्र को अल्बानियाई राज्य के साथ एक अनौपचारिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी, जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण कभी स्थापित नहीं हुआ था।

1933 नार्वे की फासीवादी पार्टी नस्जोनल समलिंग की स्थापना 17 मई, 1933 को विदकुन क्विसलिंग और जोहान बर्नहार्ड हेजोर्ट द्वारा की गई थी। इसने इस तथ्य के बावजूद नार्वे की राजनीति पर भारी प्रभाव डाला कि इसने 2.5त्न से अधिक मत कभी हासिल नहीं किए और अंतत: 1945 में भंग हो गया।

1954 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक मुकदमों में भूरा बनाम ब्राउन बोर्ड ऑफ एजुकेशन का फैसला सुनाया, जो पब्लिक स्कूलों में नस्लीय अलगाव को दर्शाता है क्योंकि %अलग शैक्षणिक सुविधाएं स्वाभाविक रूप से असमान हैं।%

1970 थोर हेयरडाल ने इसी दिन मोरक्को से यात्रा की शुरुआत की और अटलांटिक महासागर को 57 दिनों में पार कर लिया।

1973 राष्ट्रपति अभियान गतिविधियों पर सीनेट की चयन समिति ने 17 मई, 1973 को वाशिंगटन डी.सी. में वाटरगेट घोटाले की सुनवाई शुरू की।

1974 उल्स्टर वालंटियर फोर्स ने 17 मई, 1974 को आयरलैंड के डबलिन और मोनाघन में चार कार बम विस्फोट किए, जिसमें 33 नागरिक मारे गए और 300 घायल हो गए। यह गणतंत्र के इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला था।

1975 आयरलैंड के डबलिन और मोनाघन में बम धमाके में 28 लोग मारे गए।

1976 जापानी महिला श्रीमती जुनको तैबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी।

1980 दक्षिण कोरियाई सेना के जनरल चुन डू-ह्वान ने 17 मई, 1980 को देश भर में मार्शल लॉ का विस्तार किया और सरकार का नियंत्रण जब्त कर लिया। बाद में वे 1 सितंबर 1980 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने।

बरसात से पहले छतरी सही करने सरीखी सीख है मोदी की अपील

मनोज कुमार अग्रवाल

आज हम एक ग्लोबल युग में जी रहे हैं दुनिया में कहीं कुछ घटित होता है तो उसका कुछ या अधिक असर हम पर भी पड़ना तय है जैसे बरसात के सीजन से पहले झोपड़ी की खपरैल या पिनंनी की पड़ताल कर अपनी छतरी की मरम्मत करना होता है पीएम मोदी ने भी देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार की हालत संवारने के लिए देश की जनता से अपील की है। इसी बीच आज 15 मई से सरकार ने पैट्रोल डीजल के दाम में तीन रूपये लीटर का इजाफा किया है। दरअसल सरकार रोजाना तेल कंपनियों को हो रहे हजारों करोड़ रुपये के घाटे की आंशिक भरपाई के लिए धीरे-धीरे और भी रेट बढ़ा सकती है यह सरकार की मजबूरी है। आपको पता रहे विश्व के बदलते हालात ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी देश वैश्विक संकटों से पूरी तरह अलग रहकर सुरक्षित नहीं रह सकता। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब केवल युद्धक्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव कच्चे तेल की आपूर्ति, गैस, उर्वरक, खाद्य तेल, विदेशी मुद्रा भंडार और घरेलू महंगाई तक दिखाई देने लगा है। भारत जैसे विशाल और ऊर्जा निर्भर देश के लिए यह स्थिति विशेष चिंता का विषय है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचाने, गैर-जरूरी खर्च घटाने और एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील केवल सामान्य सलाह नहीं, बल्कि आने वाले आर्थिक दबावों के प्रति देश को तैयार करने का संकेत है। साथ ही यह समय की मांग भी है। इस अपील को और प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने काफिले का आकार कम करने का निर्णय लिया है। यह कदम प्रतीकात्मक होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी है। जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व मितव्ययिता को अपने आचरण में उतारता है, तो उसका संदेश नीचे तक जाता है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा में तैनात विशेष सुरक्षा दल को निर्देश दिया है कि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता किए बिना काफिले में वाहनों की संख्या कम की जाए। साथ ही, जहां तक संभव हो, नई गाड़ियां खरीदे बिना इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की दिशा में भी काम किया जाए। यह निर्णय बताता है कि संकट के समय केवल जनता से अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि नेतृत्व को स्वयं उदाहरण बनना होता है। पीएम के दौरे में उनके साथ गाडियों की लम्बी कतार अब नहीं है पीएम सिर्फ दो गाड़ी के काफिले में चल रहे हैं।

आपको बता दें करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन शुरू भी कर दिया है। हैदराबाद में उनके संबोधन के बाद गुजरात और असम में उनके काफिले में वाहनों की संख्या घटाई गई है। हालांकि सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य नियमों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यह जरूरी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि सुरक्षा व्यवस्था के भीतर भी विवेकपूर्ण खर्च और संसाधनों का संतुलित उपयोग हो। यही संतुलन आज देश के हर स्तर पर अपनाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने भी इसी दिशा में पहल की है। विधायक पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों को केवल आवश्यक वाहनों को ही

काफिले मंर रखने को कहा गया है। उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा और केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए उनके काफिले में स्वाभाविक रूप से अधिक वाहन रहते हैं। फिर भी प्रधानमंत्री की ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखते हुए काफिले को सीमित करने का निर्णय लिया। देश के अन्य मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों द्वारा भी इस तरह की पहल की जानी चाहिए। संकट के समय सरकार के बड़े पदों पर बैठे लोगों का व्यवहार जनता के मनोबल को प्रभावित करता है। आज आवश्यकता केवल सरकारी कटौती की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अनुशासन की है। वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनावों का असर अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह चिंता व्यक्त की है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया है, उसका बोझ अब तक सरकार उठा रही है। लेकिन यदि यह संकट लंबे समय तक जारी रहता है, तो आम उपभोकाओं को भी ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। यह बयान चेतावनी भी है और तैयारी का संकेत भी। भारत सरकार ने अब तक पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास किया है। इसके लिए शुल्क में कमी, नियंत्रित कीमतों में सीमित समायोजन और राजकोषीय संतुलन जैसे उपाय किए गए हैं। लेकिन कोई भी सरकार अनिश्चित काल तक अंतरराष्ट्रीय बाजार की बड़ी हुई कीमतों का पूरा बोझ स्वयं नहीं उठा सकती। यदि संकट लंबा खिंचता है, तो उसका कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं तक पहुंचना स्वाभाविक होगा। ऐसे में ईंधन की बचत केवल आर्थिक निर्णय नहीं, चल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन जाती है। भारत की पश्चिम एशिया पर निर्भरता बहुत गहरी है। हमारे कुल आयात और निर्यात का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से जुड़ा है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली राशि का बड़ा भाग भी इसी क्षेत्र से आता है। उर्वरक और गैस आपूर्ति में भी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका अर्थ है कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता केवल पेट्रोल पंपों पर कीमत बढ़ने तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर खेती, उद्योग, रसोई, परिवहन, व्यापार और रोजगार तक दिखाई दे सकता है। इसलिए इस संकट को केवल तेल संकट मानना भूल होगी। यह व्यापक आर्थिक चुनौती है। आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले झटकों का सबसे तीखा असर महंगाई पर पड़ता है। भारत में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अभी भी काफी अधिक है। यदि ईंधन महंगा होता है, तो माल बुलाई महंगी होती है। माल बुलाई महंगी होती है तो सब्जी, अनाज, दाल, दूध, निर्माण सामग्री और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। इस तरह तेल की कीमत में वृद्धि धीरे-धीरे आम आदमी की थाली तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि इस समय इंधन बचत को केवल पर्यावरण या परिवहन का मुद्दा नहीं समझना चाहिए। यह महंगाई नियंत्रण से भी सीधे जुड़ा हुआ है। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के सामने चुनौती यह है कि वैश्विक संकट का घरेलू असर सीमित रखा जाए। मौद्रिक नीति महंगाई को नियंत्रित करने का एक साधन हो सकती है, लेकिन आपूर्ति पक्ष के बड़े झटकों से केवल ब्याज दरों के सहारे नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए सरकार, उद्योग, प्रशासन और जनता सभी को मिलकर काम करना होगा। जहां सरकार खर्च में अनुशासन लाए, वहीं नागरिक भी अपनी जीवनशैली में थोड़ी सावधानी बरतें। अनावश्यक यात्रा, दिखावटी खर्च, अत्यधिक ईंधन खपत और आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम करना समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री द्वारा सोने की खरीद टालने की अपील भी इसी व्यापक आर्थिक सोच का हिस्सा है। भारत में सोना भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़े पैमाने पर सोना आयात करने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। संकट के समय यदि लोग कुछ समय के लिए सोने की गैर-जरूरी खरीद को टालते हैं, तो इससे देश को राहत मिल सकती है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल की बचत से आयात बिल कम करने में सहायता मिलेगी। छोटी-छोटी बचतें जब करोड़ों नागरिकों द्वारा की जाती हैं, तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। संकट के समय राष्ट्रों की असली शक्ति केवल सेना, मुद्रा भंडार या सरकारी नीतियों से नहीं मापी जाती। वह जनता के अनुशासन, नेतृत्व के आचरण और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी से भी तय होती है। आज भारत के सामने अवसर है कि वह संयम, मितव्ययिता और आत्मनियंत्रण के माध्यम से इस चुनौती को अवसर में बदले। प्रधानमंत्री द्वारा काफिले में कटौती का कदम इसी दिशा में एक संदेश है कि कठिन समय में शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। अब आवश्यकता है कि यह संदेश सरकार के हर विभाग, हर राज्य, हर संस्था और हर नागरिक तक पहुंचे। यह समय भय का नहीं, समझदारी का है। यह समय घचराहट का नहीं, तैयारी का है। यदि नेतृत्व उदाहरण प्रस्तुत करे और जनता सहयोग दे, तो वैश्विक संकटों का असर कम किया जा सकता है। मितव्ययिता कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्व राष्ट्र का गुण है। आज देश को यही समझना होगा कि बचाया गया ईंधन, टाली गई अनावश्यक खरीद और रोका गया फिजूल खर्च केवल व्यक्तिगत बचत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय योगदान है। कठिन दौर में संयम ही सबसे बड़ा समाधान है।

भारतीय जनमानस ने कोरोना के कठिन समय को जिस तरह अपने संयम और सदाचार से जीत लिया था अब भी पीएम की अपील के मूल भाव को समझने और उस पर अमल करने का समय है। यह परीक्षा की घड़ी है भारतीय इस संक्रमण काल को भी अपनी एकजुटता और देश के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता से पार करेंगे।

विधानसभाओं में जीत से लोकसभा की पृष्ठभूमि बना रही भाजपा!

आलोक मेहता

बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय केवल 75 वर्ष का सपना साकार होना नहीं है। इसमें उत्तर पश्चिम से पूर्वी भारत में अश्वमेध के घोड़ों से जुड़े रथ पर लगी विजय पताका में 2029 के लोकसभा चुनाव में दुगुनी सफलताओं की भाजपा की उम्मीद बंधी है। 2029 की लोकसभा राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 में अपने दम पर बहुमत से नीचे रह गई भारतीय जनता पार्टी 2029 में फिर से 272 के जादुई आंकड़े से बहुत आगे बढ़ सकती है? 2024 में भाजपा को देशभर में 240 सीटें मिलीं। सरकार बनी, लेकिन सहयोगी दलों के सहारे मजबूत बनी हुई है। अगर 2029 की राजनीति में किसी एक राज्य को सबसे निर्णायक माना जाए, तो वह पश्चिम बंगाल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहां 42 में से 12 सीटें मिली थीं। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला दिया। विधानसभा में भाजपा की बड़ी सफलता ने पहली बार यह संकेत दिया कि बंगाल अब केवल प्रतीकात्मक विस्तार का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सत्ता समीकरण बदलने वाला राज्य बन सकता है। 2026 के विधानसभा रुझान यह बताते हैं कि भाजपा ने राज्य के ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में संगठनात्मक गहराई बढ़ाई है। यदि यह रुझान कायम रहता है तो 2029 में बंगाल में भाजपा 12 सीटों से बढ़कर 24 से 30 सीटों तक पहुंच सकती है। यह अनुमान केवल अंकगणित नहीं है। बंगाल की राजनीति में यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां सीटों की संख्या 42 है। किसी एक राज्य से 10-15 अतिरिक्त सीटें मिलना राष्ट्रीय बहुमत की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि 2029 के संदर्भ में बंगाल को भाजपा का सबसे बड़ा विस्तार-क्षेत्र माना जा रहा है। 2029 की दिशा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भाजपा अब केवल अपने पारंपरिक गढ़ों के सहारे नहीं चल रही। उसकी रणनीति का नया केंद्र पूर्वी भारत बनता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में उभार, ओडिशा में मजबूती और असम में स्थिर पकड़ इस व्यापक बदलाव का संकेत है। राष्ट्रीय राजनीति में यह परिवर्तन साधारण नहीं है। लंबे समय तक भाजपा की शक्ति मुख्यतः हिंदी पट्टी और पश्चिम भारत रही। यदि बंगाल में उसे निर्णायक बढ़त मिलती है तो भारतीय राजनीति का भौगोलिक संतुलन बदल सकता है। 2029 की लड़ाई सिर्फ सत्ता बचाने की नहीं होगी। वह इस सवाल की लड़ाई होगी कि क्या भाजपा फिर से भारतीय राजनीति में अकेले बहुमत की पार्टी बन सकती है। भाजपा के पास गुजरात में 26 में से 25 , मध्यप्रदेश में सभी 29 सीट, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10, ओडिशा में 21 में से 20, दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीट हैं। अब इन्हें बनाए रखने का हर संभव प्रयास मोदी, शाह के निर्देशों से होगा। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक में पार्टी की पहले से दुगुनी सीट लाने की कोशिश रहेगी। झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र, केरल, कर्नाटक, गोवा, त्रिपुरा, केरल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम जैसे राज्यों में पहले से मिली सीटें बढ़ाने के लिए काम चल रहा है।

सनातन पर प्रहार नहीं, आत्ममंथन की आवश्यकता

कांतिलाल मांडोत

तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा में यह कहा कि लोगों को बांटने वाले सनातन धर्म को खत्म किया जाना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले वर्ष 2023 में भी उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। उस बयान पर पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन्हें यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को अपने शब्दों के परिणामों का ध्यान रखना चाहिए।

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है, लेकिन यह स्वतंत्रता किसी आस्था, संस्कृति या करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं देती। किसी भी धर्म, परंपरा या संस्कृति पर टिप्पणी करने से पहले व्यक्ति को स्वयं का आत्ममंथन करना चाहिए। विशेष रूप से तब, जब वह व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर हो या जनता के बीच प्रभाव रखता हो। शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे समाज में विचारों और भावनाओं की दिशा तय करते हैं। इसलिए सार्वजनिक मंचों पर दिया गया हर बयान जिम्मेदारी की मांग करता है। सनातन धर्म केवल एक धार्मिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक चेतना का आधार है। यह विश्व का सबसे प्राचीन जीवन दर्शन माना जाता है। जब दुनिया के अनेक हिस्सों में सभ्यता का विकास प्रारंभ भी नहीं हुआ था, तब भारत में वेद, उपनिषद, गीता और पुराण मानव जीवन के उच्चतम आदर्शों की व्याख्या कर रहे थे। सनातन ने केवल पूजा-पद्धति नहीं दी, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा, प्रकृति संरक्षण, परिवार व्यवस्था और मानवता का संदेश इसी परंपरा से निकला।

भारत की पहचान केवल उसकी सीमाओं से नहीं होती, बल्कि उसकी संस्कृति से होती है, और उस संस्कृति की आत्मा सनातन परंपरा है। मंदिर, तीर्थ, पर्व, योग, आयुर्वेद,

गीता, रामायण, महाभारत, गुरुकुल परंपरा, परिवार व्यवस्था और अतिथि देवो भव जैसे संस्कार इसी सनातन चेतना की देन हैं। आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है, भारतीय दर्शन का अध्ययन कर रही है, अध्यात्म की ओर आकर्षित हो रही है। ऐसे समय में यदि भारत में ही कुछ लोग सनातन को समाप्त करने की बात करें, तो यह केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि अपनी जड़ों से दूरी का संकेत भी माना जाएगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सनातन धर्म ने कभी किसी पर जबरन अपनी मान्यताएं नहीं थोपीं। इस परंपरा ने हमेशा विचारों की स्वतंत्रता को महत्व दिया। यहां चार्वाक जैसे नास्तिक विचारक भी सम्मानित हुए और बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुषों को भी स्थान मिला। भारत की यही विशेषता रही कि यहां मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। सनातन का मूल संदेश ही सहिष्णुता और समावेशिता है। इसलिए इसे विभाजनकारी कहना इतिहास और वास्तविकता दोनों के साथ अन्याय है।

आज एक चिंताजनक प्रवृत्ति यह भी दिखाई देती है कि हिंदू देवी-देवताओं और सनातन परंपराओं पर टिप्पणी करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गया है। फिल्मों, राजनीति, सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर बार-बार हिंदू आस्थाओं को निशाना बनाया जाता है। जबकि अन्य धर्मों के प्रति वही लोग अत्यधिक सावधानी बरतते हैं। यह दोहरा रवैया समाज में असंतुलन पैदा करता है। यदि वास्तव में समानता और धर्मनिरपेक्षता की बात करनी है, तो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान होना चाहिए। केवल सनातन को निशाना बनाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

सनातन धर्म को मिटाने की बातें करने वाले शायद यह भूल जाते हैं कि यह परंपरा किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल पर आधारित नहीं है। यह हजारों वर्षों से चली आ रही आध्यात्मिक धारा है। अनेक आक्रमण हुए, विदेशी शक्तियां आईं, मंदिर तोड़े गए, संस्कृति को कमजोर करने के प्रयास हुए, लेकिन सनातन हर बार और अधिक शक्ति के साथ खड़ा हुआ। क्योंकि इसकी जड़ें केवल जमीन में नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन में हैं।

भारत को देवभूमि और कर्मभूमि कहा जाता है। भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण, भगवान शिव, माता दुर्गा और अनेक दिव्य परंपराएं इसी भूमि से जुड़ी हैं। यह वही भूमि है जहां ऋषियों ने तप किया, जहां वेदों की रचना हुई और जहां मानवता को धर्म का मार्ग मिला। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सनातन केवल एक धर्म नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। जिस राष्ट्र की आत्मा इतनी प्राचीन और गहरी हो, उसे समाप्त करने की कल्पना भी संभव नहीं है।

राजनीति में विचारों का संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना खतरनाक प्रवृत्ति है। नेताओं को समझना चाहिए कि वे केवल अपने समर्थकों के नहीं, पूरे समाज के प्रतिनिधि होते हैं। उनके शब्द करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा कोई बयान देने से बचना चाहिए जिससे समाज में तनाव या विभाजन पैदा हो।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी धर्मों और परंपराओं के प्रति सम्मान की भावना रखी जाए। किसी भी धर्म की आलोचना करने से पहले उसके इतिहास, दर्शन और योगदान को समझना चाहिए। सनातन धर्म ने विश्व को शांति, सह-अस्तित्व और मानवता का संदेश दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी अवधारणाएं आज भी पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक हैं। सनातन को मिटाने की बातें करने वाले आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन सनातन की धारा अनंत काल तक बहती रहेगी। क्योंकि यह किसी सत्ता का नहीं, सत्य का मार्ग है।

16 राज्यों में महासत्यापन चुनाव आयोग के लिए चुनौती

सनत जैन

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हाल ही में खत्म हुए हैं। इसके तुरंत बाद भारत निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 36 करोड़ मतदाताओं के सत्यापन के लिए एसआईआर की अधिसूचना जारी कर दी है। अभी तक चुनाव आयोग ने दो चरणों में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 59 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन का काम किया है। इसमें अभी तक 5.50 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाये गये हैं। इसको लेकर लगातार विवाद देखने में मिलते रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी तक इस पर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आया है। चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है, उसका अधिकार उसे है या नहीं, अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले से इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसी बीच बिहार सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। चुनाव आयोग ने यहां के लिए जो नियम बनाए थे, वह बिहार एवं अन्य राज्यों के नियमों से अलग थे। पश्चिम बंगाल में करीब 1 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। करीब 63 लाख मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में होते हुए भी स्पेलिंग या अन्य कारणों से हटाए गए थे। इसमें से करीब 28000 मतदाताओं ने ट्रिब्यूनल में अपील भी की है। उन मतदाताओं को मतदान में भाग नहीं लेने दिया गया। पिछले तीन माह में एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों और उन नागरिकों के बीच में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनका अधिकार छीन लिया गया है।

प. बंगाल में एसआईआर के बाद ममता सरकार

बुरी तरह से पराजित हुई है। जितने नाम एसआईआर में हटाये गए, उससे कम मतों से टीएमसी के उम्मीदवार पराजित हुए हैं। यह विवाद चल रहा था, इस बीच रही-सही कसर बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने जलती हुई आग में घी डालने का काम किया है। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा। जो मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें सरकारी स्तर पर जो सुविधाएं मिल रहीं थीं, वह आगे नहीं मिलेंगी।

इसी बीच चुनाव आयोग द्वारा 36 करोड़ मतदाताओं को एसआईआर के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे आसानी से स्वीकार किया जाएगा, इसमें संदेह है। सुप्रीम कोर्ट से अभी तक चुनाव आयोग को एसआईआर को लेकर एक तरह का संरक्षण मिलता रहा है। अब जिस तरह से प्रतिक्रिया हो रही है, उससे चुनाव आयोग की चुनौतियां भविष्य में बढ़ती हुई दिख रही हैं। सुप्रीम में जो सुनवाई चल रही है, उसमें न्यायपालिका के ऊपर याचिकाकर्ताओं का दबाव बनना शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग एसआईआर का काम करा पाएगा या नहीं, इसमें संदेह है। विपक्ष इस मामले में जिस तरह से एकजुट हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी का असर अब आम जनता को सीधे प्रभावित कर रहा है। यह मामला अब केवल चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रह गया है। इसे नागरिक अधिकार से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। यह अधिकार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग मतदाता को भारतीय नागरिक है, या नहीं, इस आधार पर मतदाताओं के नाम कैसे काट सकता है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार ने राज्य सरकार की सुविधायें बंद करने और नागरिक नहीं मानने की बात कहना शुरू कर दी है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले में निर्णय देने का दबाव बनेगा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्षी दलों को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। वह सरकार के इशारे पर भाजपा को मदद कर रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में महाभियोग पेश हो चुका है। जिस कानून के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती देते हुए याचिका लगाई गई, जिस पर सुनवाई चल रही है। अगले साल कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे। यह बात अब स्पष्ट रूप से समझ आने लगी है। 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार के इशारे पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण के नाम पर एक विशेष वर्ग के नाम मतदाता सूची से काटने की जो मुहिम चुनाव आयोग ने चला रखी है, इसका विरोध करने के लिए नागरिक और राजनीतिक दल अब सड़कों पर उतरेंगे। चुनाव आयोग के लिए अब एसआईआर का काम इतना आसान नहीं होगा, जितना चुनाव आयोग सोच रहा है। वर्तमान स्थिति में जनगणना का काम शुरू हो गया है। बहुत बड़ा सरकारी अमला जनगणना के काम में लगा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर आम जनता वैसे ही नाराज है। जिस तरह से मतदाता सूची सत्यापन के लिए मतदाताओं को परेशान होना पड़ रहा है, वह आग में घी डालने की तरह हो सकता है। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है।

बंगाल में शुभ राज के साथ सनातन का सूर्योदय

मृत्युंजय दीक्षित

पश्चिम बंगाल में 69 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार प्रथम सरकार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कार्यभार ग्रहण करके काम पर लग गयी है। बंगाल में बीजेपी की विजय बहुत बड़ी व ऐतिहासिक है। बंगाल ही नहीं भारत के अन्य भागों में भी इस विजय का आनंद दिखाई वातावरण दे रहा है। इस विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक, तेलंगना और गुजरात के दौरे में जो भीड़ उमड़ रही है उससे स्पष्ट रूप से जनसामान्य और भाजपा कायकर्ताओं के उत्साह का अनुमान लगाया जा सकता है। बंगाल विधानसभा चुनावों मे हिंदू समाज ने पहली बार बांग्लादेशी घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टिकरण की विकृत राजनीति के विरुद्ध एकजुट होकर मतदान किया और जिसका परिणाम आज पूरा भारत देख रहा है। बंगाल की जिस धरती पर 75 वर्ष पूर्व डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की वैचारिक नींव रखी थी उसी बंगाल में पहली बार भाजपा 27 सीटों के साथ सत्ता के शिखर पर पंहुची और भगवा वस्त्रों में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बंगाल की कैबिनेट में अभी पांच मंत्रियों को ही शपथ दिलाई गई है, जिसमें बंगाल में भाजपा का संगठन खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले दिलीप घोष, फैशन डिजाइनर से बंगाल भाजपा की सबसे मुखर नेत्री बनी अग्निमित्रा पॉल जिन्होंने तृणमूल के खिलाफ आक्रामक मोर्चा संभाला, बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थी मतुआ समुदाय के प्रमुख चेहरे अशोक कीर्तनिया जो उत्तर 24 परगना जिले के भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे इलाको में भाजपा के जमीनी संगठनकर्ता के रूप मे अत्यंत सक्रिय रहे हैं, छात्र राजनीति से उभरे नेता निशीथ प्रामाणिक जो 2019 में भाजपा से जुड़े और जंगल महल के आदिवासी समुदाय के बड़े नेता खुदीराम टुडू शामिल हैं। अभी इस मंत्रिमंडल है का विस्तार होना बाकी है। बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप लघु भारत के भव्य दर्शन हो रहे थे तथा भविष्य की राजनीति के संकेत भी मिल रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक बंगाल में कांग्रेस, वामपंथ और तृणमूल की सरकारें रहीं जो तुष्टिकरण में आकंठ डूबी रहीं और हिंदुओ को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। स्थितियां इतनी विकट हो गयी थीं कि बंगाल की धरती पर जय श्रीराम बोलने पर नफरत का कहर टूट पड़ता था। आज उसी बंगाल में जब जयश्रीराम के नारे गूंज रहे हैं तो बंगाल का हर सनातनी खुशी से सराबोर हो रहा है। बंगाल में भाजपा सरकार आने से पश्चिम बंगाल के हिन्दुओं को तुष्टिकरण की दमनकारी नीतियों और भय के माहौल से आजादी मिली है। यह विजय केवल सत्ता का परिवर्तन नही अपितु बंगाल के पुनरुत्थान का शंखनाद है। अब बंगाल सही मायने में सोनार बांग्ला बनने की ओर अग्रसर होगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व आर्थिक उत्थान के नए दौर मे प्रवेश करेगा। हार की कुंठा से ग्रसित तृणमूल व विरोधी दलों के नेता अभी भी एसआईआर, चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षाबलों वाले आरोप दोहरा रहे हैं जबकि वास्तविकता यह है कि भाजपा ने यह चुनाव लम्बे संघर्ष और अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान के बाद जीता है। तृणमूल के राज में वर्ष 2011 से 2025 के बीच भाजपा के 321 कार्यकर्ता मारे गए, उनके विरुद्ध हुई हिंसा में हजारों घर उजाड़ दी गए, भाजपा व संघ के किसी कार्यकर्ता को बम से उड़ाया गया किसी को पेड़ से लटकाया गया। 2021 की चुनावी हिंसा में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए किंतु ममता सरकार उन सभी में अड़ंगा डालती रही। आज संदेशखाली से आर जी कर कांड तक सभी पीड़ित परिवारों के मन में एक नया सबेरा आया है कि अब न्याय होकर रहेगा। बंगाल के हिंदू जनमानस को नयी सरकार पर भरोसा है इसलिए नई सरकार को भी अत्यंत तत्परता और सतर्कता के साथ संकल्प पत्र को पूरा करना होगा।

टमाटर की उन्नत कृषि कार्यमाला

टमाटर अत्यंत ही लोकप्रिय तथा पोषक तत्वों से युक्त फलदार सब्जी है। जिसका उपयोग साल भर किया जाता है। सब्जी के अलावा उससे सूप, चटनी, सलाद, आदि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। विटामिन व अन्य खाद्य पदार्थ उपयुक्त मात्रा में पाये जाते हैं।

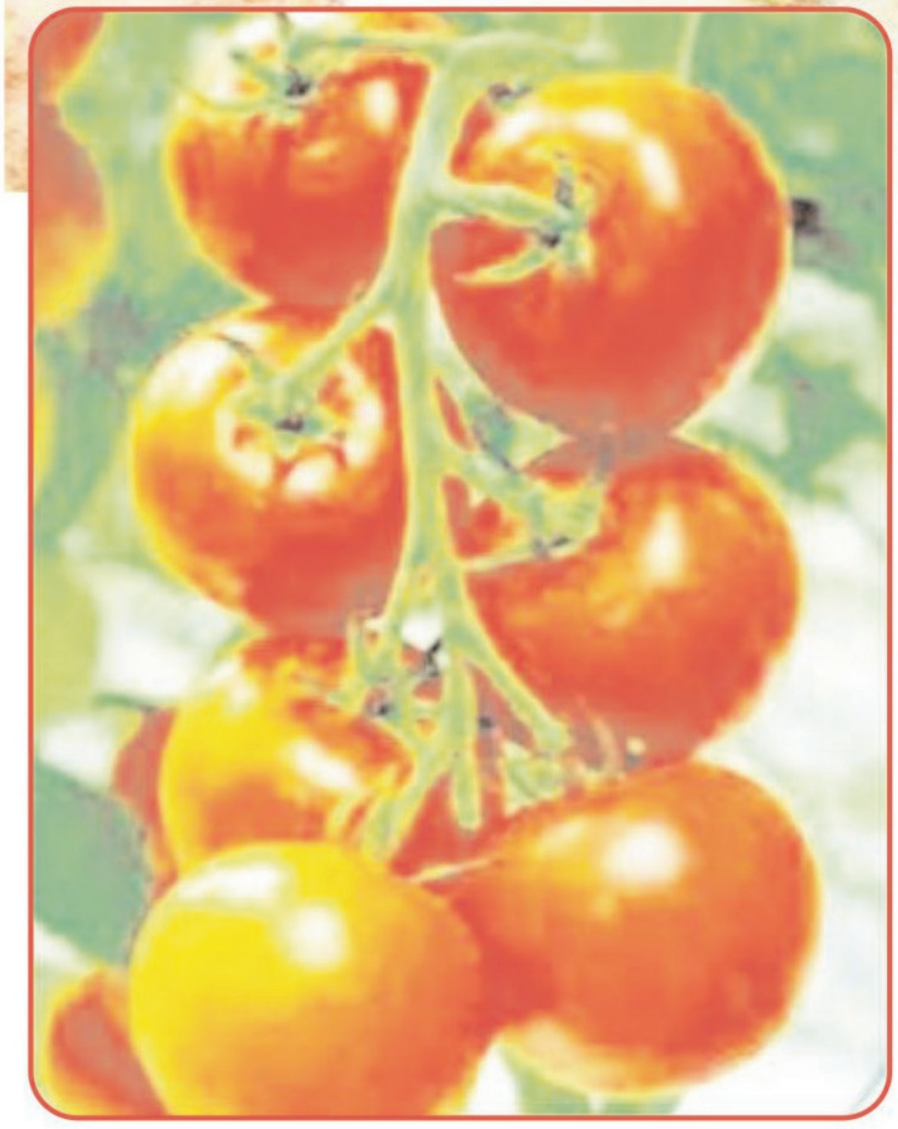

भूमि- टमाटर की खेती कई किस्मों की मिट्टी में की जाती है लेकिन अच्छी जल निकासी चिकनी मृदा तथा दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है।

खेत की तैयारी :- प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2-3 बार कल्टीवेटर या हैरो चलाना चाहिए ताकि भूमि की निचली कठोर परत टूट जाए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए।

उन्नतशील किस्में :- पूसा रूबी, पन्त टी-1 पंजाब छुआरा, अर्का विकास, पूसा अर्ली ड्वार्फ आदि।

बीज दर:- देशी - 400-500 ग्राम/ हेक्टेयर संकर - 100 ग्राम / हेक्टेयर

पौध तैयार करना (नर्सरी):- वर्षा ऋतु में 10 सें.मी. ऊंची क्यारी तैयार कर उसमें बीज बोना चाहिए। बीज कतारों में बोना चाहिए।

बीजोपचार :- बीज को बोने से पूर्व थायरम या बाविस्टिन से 2 ग्राम/ किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।

बुआई का समय :- खरीफ- जून-जुलाई, शीत -अक्टूबर- नवम्बर

रोपण :- क्यारियों में जब पौधे 4 से 5 सप्ताह के हो जाएं या 7 से 10 सें.मी. के हो जाएं तब खेत में रोपित करना चाहिए। पौध रोपण के पश्चात् तुरन्त हल्की सिंचाई करनी चाहिए। एक स्थान पर एक ही पौधा लगाएं।

पौध अन्तरण:- कतार से कतार की दूरी 75 सें.मी. एवं पौध से पौध की दूरी 60 सें.मी. रखना चाहिए।

उर्वरक की मात्रा :- गोबर खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भूमि की तैयारी के समय मिलाना चाहिए। यूरिया 217 किलो प्रति हेक्टेयर, तीन भागों में देना चाहिए। पहला भाग, पौध रोपण के समय तथा दूसरा भाग एवं तीसरा भाग 30 दिन के अन्तर से देना चाहिए। एस.एस.पी. 500 किलो/ हेक्टेयर व पोटाश 100 किलो प्रति हेक्टेयर पौध रोपण के समय देना चाहिए।

सिंचाई :- टमाटर में अधिक तथा कम सिंचाई दोनों ही हानिकारक हैं। शरद ऋतु में 10 से 12 दिन के अन्तर तथा गर्मी में 4-5 दिन के अन्तर में भूमि के अनुसार सिंचाई की जा सकती है।

निंदाई गुड़ाई :- टमाटर की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए निरंतर निंदाई-गुड़ाई करते रहना आवश्यक है। गुड़ाई उथली करनी चाहिए जिससे जड़ों को नुकसान न पहुंचे। 30-40 दिन बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए।

वृद्धि नियामकों का प्रयोग :- वृद्धि नियामकों का प्रयोग फूलों को झड़ने से रोकने तथा बिना निषेचन के फलों को विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। पी.सी.पी.ए. 50-100 पी. पी. एम. (50-100 मि.ग्रा./ लीटर पानी में घोलना है) के घोल का छिड़काव लाभकारी होता है।

सहारा देना :- ऊंचाई व मध्यम ऊंचाई वाली किस्मों को पेड़ की टहनियां (बांस) की सहायता से सहारा देना चाहिए, ऐसा करने से पौधे की वृद्धि अच्छी होती है, वर्षा ऋतु में फल तथा पेड़ सड़ते नहीं हैं। फलों का आकार बढ़ जाता है तथा पैदावार भी अधिक होती है।

फलों की तुड़ाई :- टमाटर के फसल की तुड़ाई कई अवस्थाओं में की जाती है-

कच्चे या हरे फल :- टमाटर को अधपके हरे से गुलाबी पड़ने पर तब तोड़ा जाता है जब इसे दूर स्थित बाजारों में विपणन हेतु भेजना होता है।

गुलाबी या हल्के लाल फल:- टमाटर को गुलाबी या हल्के लाल होने की अवस्था में तब तोड़ा जाता है जब इसे स्थानीय बाजारों में भेजना होता है।

पके हुए टमाटर :- फलों का अधिकतम भाग लाल होता है व नरम होता है ऐसे फल घरेलू उपयोग या कच्चे सलाद खाने के काम आते हैं।

अधिक पके टमाटर :- बीज उत्पादन के लिए लाल फल आदर्श माने जाते हैं। फल परीरक्षण के लिए भी अधिक पके टमाटर अच्छे माने जाते हैं।

गोभीवर्गीय में पोषक तत्वों की आवश्यकता

भूरापन या ब्राउनिंग - यह समस्या गोभीवर्गीय फसलों में बोरान की कमी से होता है।

लक्षण - भूरापन में शुरूआत में फूल में जल अवशोषित धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि बाद में बड़े हो जाते हैं। इसके बाद तने में भी जल अवशोषित धब्बे पड़ते हैं तथा तना अंदर से खोखला हो जाता है। यदि भूरापन का प्रकोप ज्यादा होता है तो पूरा फूल में कुछ दिन बाद गुलाबी या भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं।

उपचार - बोरान की कमी को दूर करने के लिये 10-15 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टर भूमि में पौध रोपण के समय देना चाहिए अथवा जब फसल खड़ी हो 0.1 प्रतिशत बोरेक्स घोल का छिड़काव करना चाहिए प्रथम छिड़काव पौध रोपण के दो सप्ताह पश्चात और दूसरा छिड़काव फूल बनने से दो सप्ताह पहले करना चाहिए।

व्हिपटेल - यह लक्षण गोभीवर्गीय फसलों में मालीब्डिनम नामक तत्व की कमी के कारण होता है।

लक्षण - मुख्यत: मालीब्डिनम की कमी अम्लीय भूमि में हो जाती है अर्थात् मालीब्डिनम अनुपलब्ध रूप से हो जाता है, जिससे पौधे इस तत्व का अवशोषण नहीं कर पाते और व्हिपटेल के लक्षण दिखाई देते है, इसमें शुरूआत में पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियाँ सिकुड़ कर सफेद पड़ने लगती हैं तथा कुछ दिन बाद पत्तियां अपना आकार खो देती हैं और मिडरिब के अलावा शेष भाग सूख जाता है, जिसके कारण इसे सामान्यत: व्हिपटेल कहा जाता है।

उपचार - मालीब्डिनम की कमी को दूर करने के लिए अम्लीयता कम करने के उद्देश्य से 50-70 क्विंटल बुझा चूना प्रति हेक्टर खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही पौध रोपण के पहले 2.5 से 5 किलो सोडियम मालीब्डेट प्रति हेक्टर भूमि में मिला देना चाहिए अथवा खड़ी फसल में 0.05ज सोडियम मालीब्डिट घोल का पौधों पर छिड़काव करना चाहिए।

बटनिंग - बटनिंग की समस्या गोभी वर्गीय फसलों के कई कारणों से होती है जैसे अधिक उम्र के रोप के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण या समय के अनुसार उचित किस्मों को ना लगाने से ऐसा होता है।

लक्षण - फूलों का विकसित ना होकर छोटा रह जाना बटनिंग कहलाता है। इसमें फूलों का आकार छोटा हो जाता है तथा कम विकसित पत्तियाँ होती हैं।

उपचार - बटनिंग को रोकने के लिये अगेती या पिछेती किस्में अनुशंसित समय पर ही लगाएं, पौधे की वृद्धि चाहे वह नर्सरी में हो या खेत में नहीं रूकनी चाहिए। अधिक सिंचाई न करें। जो पौधा नर्सरी में अधिक दिन के हो उन्हें खेत में न लगाएं और नाइट्रोजन की उचित मात्रा पौधों को समय-समय पर दें।

रेसीयनेस - रेसीयनेस के लक्षण मुख्यत: वातावरण में अनुकूल तापमान की कमी, अधिक नाइट्रोजन देने के कारण तथा अधिक आर्द्रता के कारण होती हैं।

लक्षण - समय से पूर्व अविकसित कली को रेसीयनेस कहते हैं। इसमें फूल की ऊपरी सतह ढीली पड़ जाती है तथा सफेद छोटी कलिका बन जाती है।

उपचार - रेसीयनेस से उपचार के लिये उचित किस्म का चयन करें, समय पर पौधों की रोपाई करें, नाइट्रोजन की उचित मात्रा का प्रयोग करें तथा प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें।

अन्धता - अन्धता गोभीवर्गीय फसलों से पौधे की वृद्धि के शुरूआत मुख्य कलिका में कीट के प्रकोप के कारण तथा वातावरण में तापमान में कमी होने वाला पाला पड़ने के कारण होता है।

लक्षण - अन्धता में पौधे की मुख्य कलिका कीट के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा इसके पत्ते बड़े, चमड़े जैसे मोटे और गहरे रंग के हो जाते हैं।

उपचार - अन्धता की रोकथाम के लिए मुख्य कलिका को कीटों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, उचित किस्म का चयन करना चाहिए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी पेपरलीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं : राहुल

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग करते हुए कहा है कि यदि उन्हें नहीं हटाया जाता है तो श्री मोदी को स्वयं इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। श्री गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में कहा, मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन श्री मोदी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी हटाइए या जवाबदेही खुद लीजिए।उन्होंने आरोप लगाया कि इस पेपरलीक की घटना से देश के 22 लाख विद्यार्थियों की दो वर्ष की मेहनत बर्बाद हो गई और पूरा देश जानता है कि नीट परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर प्रश्नपत्र बांटा जा रहा था। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने इस मामले से खुद को अलग बताते हुए संसदीय समिति की सिफारिशों को भी अनदेखा किया था।

भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है: सीजेआई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने अपनी हालिया कॉकरोच टिप्पणी पर गहरा दुख व्यक्त कर स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने उन रिपोर्टों को खारिज किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से की थी। सीजेआई ने कहा कि उनकी आलोचना उन लोगों पर केंद्रित थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों का इस्तेमाल करके कानूनी पेशे में घुसपैठ कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि उन्होंने युवा वकीलों को कॉकरोच कहा था। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई सूर्यकांत ने शनिवार को इस बात से इंकार करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया। अपने स्पष्टीकरण में, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने कल एक बेबुनियाद मामले की सुनवाई के दौरान मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया।

होर्मुज पर ईरान का कमिटमेंट: भारत को मिला सुरक्षा का आश्वासन

नई दिल्ली (ईएमएस)। होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ती अस्थिरता और भारतीय जहाज पर हालिया हमले के बाद, ईरान ने भारत को व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दे दिया है। यह कदम नई दिल्ली के लिए राहत लेकर आया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात कर क्षेत्रीय स्थिति और होर्मुज की सुरक्षा पर चर्चा की। विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि ईरान हमेशा होर्मुज की सुरक्षा के संरक्षक की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाता रहेगा और अपने मित्र देशों के लिए भरोसेमंद साझेदार है। यह आश्वासन ओमान के पास एक भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुए हमले के बाद आया है, जिसे भारत ने अस्वीकार्य बताया था। वर्तमान में, करीब 13 भारतीय जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार करने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहाजों को सुरक्षित मार्ग के लिए ईरानी सेना से संपर्क करना होगा क्योंकि इलाके में बारूदी सुरंगें और अन्य खतरे मौजूद हैं।

महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की बैलगाड़ी यात्रा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी नेताओं ने प्रतीकात्मक बैलगाड़ी यात्रा निकालकर पेट्रोल, डीजल, दूध, सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान सरकार पर आम जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देविंदर यादव के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। उन्होंने पारंपरिक बैलगाड़ी पर सवार होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर कहा कि बेलगाम महंगाई ने आम लोगों का जीवन दूभर किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है। दूध, सब्जियां, रसोई गैस और अन्य घरेलू सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को मिली नियमित जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को शिकोहपुर जमीन सौदा मामले में प्री-अरेस्ट बेल यानी नियमित जमानत दे दी गई। कोर्ट ने इस मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए वाड्रा को समन जारी किया था। जमानत देते समय कोर्ट ने कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी। सुनवाई के दौरान वाड्रा ने कहा कि ईडी सरकार के इशारे पर काम करती है और निष्पक्ष नहीं है, लेकिन मुझे देश की न्यायपालिका पर पूरा यकीन है।

वहीं, ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने जांच की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एजेंसी अभी भी कुछ पहलुओं की जांच कर रही है और इसके लिए समय की जरूरत है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ईडी के मुताबिक वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। बाद में इसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया।

गरीबों के इलाज में भरपूर मदद करेगी सरकार: सीएम योगी

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद की गुहार लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया कि उपचार कराने में सरकार भरपूर मदद करेगी और इसके लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों से मिले। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगो तक जाकर उनकी समस्याओं को सुना। उनके प्रार्थना पत्र लिए और पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए।अलग.अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषप्रद होना चाहिए।

जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद का अनुरोध करने आए थे। एक महिला ने अपने बच्चे के इलाज में आर्थिक दिक्कत और आयुष्मान कार्ड न होने की समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता मत करिए। बच्चे का इलाज जरूर होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और विवेकाधीन कोष से इलाज में आर्थिक सहायता देंगे। एक अन्य महिला को भी उन्होंने इन्हीं शब्द भावों का आत्मीय संबल दिया। इलाज संबंधी प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए योगी ने कहा कि इस्टीमेट की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर शासन को उपलब्ध करा दें।अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी पुलिस अधिकारियों को अपराधियों व भू माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को खूब दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया

सेना प्रमुख की पाकिस्तान को दो टूक

आतंकवाद का समर्थन करेगा तो मिटा दिया जायेगा मानचित्र से

नयी दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि उसे तय करना होगा कि वह विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है या आतंकवादियों को आश्रय देने और भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण गतिविधि जारी रखकर खुद को इतिहास से मिटाने का जोखिम लेना चाहता है।शनिवार को यहां मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक संवाद सत्र में यह पूछे जाने पर कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी परिस्थितियां फिर से उत्पन्न होती हैं तो भारतीय सेना कैसा जवाब देगी, तो जनरल द्विवेदी ने दो टूक उत्तर देते हुए कहा, ऽअगर आपने पहले मेरी बातें सुनी हैं, तो मैंने कहा है कि पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को पनाह देता रहा और भारत के खिलाफ गतिविधियां करता रहा, तो उसे तय करना होगा कि वह भौगोलिक मानचित्र का हिस्सा रहना चाहता है या इतिहास का।

सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत के शीर्ष सैन्य नेतृत्व की ओर से एक मजबूत चेतावनी के रूप में देखी जा रही है जो यह संकेत देती है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत की सहनशीलता सीमित है और भविष्य में कोई भी भड़काने वाली कार्रवाई का निर्णायक जवाब दिया जायेगा।जनरल द्विवेदी ने पिछले वर्ष नवंबर में %चाणक्य डिफेंस डायलॉग% को संबोधित करते हुए कहा था , ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ट्रेलर था, जो 88 घंटे में समाप्त हुआ। हम भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान अवसर देगा, तो हम उसे यह सिखाएंगे कि पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से व्यवहार कैसे करना चाहिए।ऑपरेशन सिंदूर के समय सैन्य संचालन महानिदेशक रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ पर कहा था कि भारत की सैन्य कार्रवाई के कारण पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा पर भारी नुकसान उठाना पड़ा जिसके बाद उसे भारत के सामने संघर्षविराम की गुहार लगानी पड़ी।

चीन-अमेरिका टकराव दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है : वांग यी

बीजिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वार्ता के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच टकराव दोनों देशों और पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है।चीन सेंट्रल टेलीविजन (सीसीटीवी) के अनुसार, वांग यी ने कहा, चीन और अमेरिका के बीच टकराव दोनों देशों और पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा, जबकि सहयोग से कई ऐसे महान परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जिनसे दोनों देशों और पूरी दुनिया को लाभ होगा।मंत्री ने आगे कहा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होने के नाते चीन और अमेरिका एक-दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते।

मंत्री ने आगे कहा, (चीन और अमेरिका के बीच संबंध) प्रबंधनीय और स्थिर होने चाहिए, न कि लगातार उतार-चढ़ाव वाले रोलर कोस्टर की तरह।चीन के शीर्ष राजनयिक ने बताया कि शी और ट्रंप के बीच लगभग नौ घंटे की बातचीत हुई।चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, वांग यी ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने गहन चर्चा की और फलदायी परिणाम प्राप्त किए। बैठक में औपचारिक वार्ता और स्वागत भोज के साथ-साथ विचारों का आदान-प्रदान और छोटे पैमाने पर दौरे भी शामिल थे।

ईरान के साथ युद्धविराम पाकिस्तान के अनुरोध पर किया: ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पश्चिम एशिया में शत्रुता को समाप्त करने के लिए राजनयिक मार्ग खोलने के उद्देश्य से ईरान के साथ किया गया युद्धविराम समझौता पाकिस्तान के अनुरोध पर किया गया था। श्री ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका शत्रुता में आये इस ठहराव को समझौते के रूप में नहीं, बल्कि अपने अत्यधिक शक्तिशाली होने की स्थिति से देखता है। उन्होंने दुनिया के सबसे अशांत क्षेत्रों में से एक में पाकिस्तान की राजनयिक भूमिका की प्रशंसा करते हुये कहा।

देश के 19 से अधिक राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश की चेतावनी

नयी दिल्ली। मौसम विभाग ने देश के 19 से अधिक राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है जबकि बिहार और अंडमान में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं चलने की चेतावनी दी है।दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान आसमान आम तौर पर साफ रहा।

मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि मानसून आज दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व हिस्सों, अंडमान सागर के अधिकांश क्षेत्रों, संपूर्ण निकोबार द्वीप समूह और श्री विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस बार मानसून समय से पहले केरल पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून के 26 मई के आसपास केरल पहुंचने के आसार हैं , हालांकि इसमें चार-पांच दिन की घटत-बढ़त हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों और गर्मी से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है।

खेल
प्रमुख समाचार

सात्विक-चिराग थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंचे

बैंकॉक। सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सात्विक-चिराग ने शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में मलयेशिया के गोह जी फेई और नूर इजुद्दीन की जोड़ी को हराया। विश्व की चौथी नंबर कू जोड़ी सात्विक-चिराग ने 2019 और 2024 में यहां खिताब जीता था।

इस भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में विश्व की नौवें नंबर की मलयेशियाई जोड़ी के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया और 82 मिनट तक चले मुकाबले में 19-21, 22-20, 21-16 से जीत दर्ज करने में सफल रहे। सात्विक-चिराग की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में तीसरी बार पहुंची है, जबकि मौजूदा सीजन में इस जोड़ी का यह किसी टूर्नामेंट का पहला खिताबी मुकाबला होगा।

सात्विक-चिराग की जोड़ी का गोह जी फेई और नूर इजुद्दीन के खिलाफ 8-2 का रिकॉर्ड हो गया है। हालांकि, इस मलयेशियाई जोड़ी ने पिछले साल सात्विक-चिराग को इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में मात दी थी। सात्विक-चिराग का फाइनल में पहुंचना भारत के लिए राहत की खबर है क्योंकि शुक्रवार को महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधू और पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में अपने-अपने मुकाबले हारकर बाहर हो गए थे। अब सात्विक-चिराग से ही इस टूर्नामेंट में खिताब जीतने की उम्मीद है।

मलयेशियाई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करके 3-1 की बढ़त बना ली, लेकिन सात्विक और चिराग ने स्कोर 5-5 से बराबर कर लिया। पहले गेम में मलयेशियाई जोड़ी ने ब्रेक तक 11-8 की बढ़त बना ली। चिराग की गलती से शटल नेट में चली गई और अंतर बढ़ गया। पहला गेम मलेशियाई जोड़ी ने 21-19 से जीता।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों के मुनाफे पर भी दिया झटका

नईदिल्ली। पेट्रोल और डीजल पर आम जनता को झटका देने के बाद अब सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों के मुनाफे पर भी बड़ा झटका दिया है। सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों के विदेशी मुनाफे पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 3 रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल गेन्स टैक्स लगा दिया है। यह नई दरें 16 मई से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब विदेशों में पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को प्रति लीटर 3 रुपए का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) देना होगा। सरकार ने पहली बार पेट्रोल पर एसएईडी टैक्स लगाया है। हालांकि, सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर राहत देते हुए एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की है। डीजल पर लेवी घटाकर 16.5 रुपए प्रति लीटर और जेट फ्यूल पर 16 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है।

एनएचपीसी का लाभ चौथी तिमाही में 68 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी का वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 68 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1,549.42 करोड़ रुपए रहा। एनएचपीसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की जनवरी-मार्च तिमाही में उसने 919.63 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। चौथी तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 3,120.52 करोड़ रुपए हो गई, जो 2024-25 की समान तिमाही में 2,557.71 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का शुद्ध लाभ 4,220.46 करोड़ रुपए रहा, जबकि 2024-25 में यह 3,411.73 करोड़ रुपये था। इसी अवधि में कुल आय बढ़कर 12,686.09 करोड़ रुपए हो गई, जो 2024-25 में 11,614.61 करोड़ रुपए थी। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 21 पैसे के अंतिम लाभांश को भी मंजूरी दी है।

रुपए गिरती रही तो ईंधन मूल्य वृद्धि का लाभ खत्म हो जाएगा

नई दिल्ली। रुपए में यदि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और भी गिरावट होती है तो तेल विपणन कंपनियों को वाहन ईंधन कीमतों में की गई बढ़ोतरी से मिलने वाला पूरा लाभ खत्म हो सकता है। एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने यह कहा। एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट के मुताबिक, ईंधन कीमतों में यह बढ़ोतरी तेल विपणन कंपनियों को खुदरा बिक्री पर लागत के मुकाबले हो रहे नुकसान (अंडर-रिकवरी) में करीब 52,700 करोड़ रुपए की राहत दे सकती है, जो वित्त वर्ष 2026-27 में अपेक्षित कुल नुकसान का लगभग 15 प्रतिशत है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। रिपोर्ट कहती है कि रुपए में अगर आगे भी गिरावट का रुख बना रहता है तो कच्चे तेल के आयात की लागत बढ़ जाएगी, जिससे कीमत वृद्धि का पूरा लाभ समाप्त हो सकता है।

एआई अब सिर्फ तकनीक नहीं बना कारोबार का आधार

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब व्यवसायों के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त तकनीकी परत नहीं रह गया है, बल्कि यह तेजी से वैश्विक उद्यमों के लिए बुनियादी ढांचा बनता जा रहा है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कंपनी की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में यह बात कही है। एआई के दम पर शानदार वित्तीय नतीजे और नई भर्तियों में वापसी इस बात का संकेत है कि आईटी सेक्टर में बड़े बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। चंद्रशेखरन ने बताया कि टीसीएस ने अपने ह्यूमन+एआई परेटिंग मॉडल के विस्तार में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मॉडल के तहत कंपनी ने एआई सेवाओं से 2.3 अरब डॉलर का सालाना राजस्व हासिल किया है।

अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग, पक्ष-विपक्ष को गंभीरता से विचार करना होगा

शंकर अय्यर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सादगी और संयम का उपदेश देकर लोगों की सामाजिक चेतना को जगाया। बढ़ती कीमतों के दबाव और पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण पैदा हुई अनिश्चितता के बीच, प्रधानमंत्री का जोशीला भाषण आत्मनिर्भरता की अवधारणा के इर्द-गिर्द राष्ट्रीय आम सहमति बनाने का एक प्रयास था।

पिछले हफ्ते अप्रैल महीने में जीएसटी से हुई रिकॉर्ड 2.43 लाख करोड़ रुपये की कमाई छाई रही। इन आंकड़ों ने सरकार को दुविधा में डाल दिया। असल में जीएसटी के आंकड़ों से पता चला कि घरेलू बिक्री में सिर्फ 4.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि आयात से होने वाली जीएसटी कमाई में 25.8 फीसदी का जबर्दस्त उछाल आया। आयात की लागत में यह बढ़ोतरी असल में पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का ही नतीजा है।

होर्मुज जलडमरूमध्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की जीवन-रेखा है। बढ़ती मांग और आपूर्ति में रुकावट का असर कीमतों पर पड़ता है। भारत को सिर्फ कच्चे तेल के लिए जो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, उससे भारत के आयात बिल में 70 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होने की आशंका है, क्योंकि भारत में कच्चे तेल के आयात की कीमत 100 से 130 डॉलर प्रति बैरल के बीच है। चूंकि दुनिया भर में गैस की आपूर्ति कम हो गई है, इसलिए भारत को उतनी ही कीमत चुकानी पड़ रही है, जितनी मांगी जा रही है। बढ़ती आयात लागत के चलते रुपया 95 रुपये प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर चुका है। जानकारों का मानना है कि यह 100 का आंकड़ा भी छू सकता है।

असल में, चुनावी मौसम के कारण भारत सरकार ने उन पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

नहीं बढ़ाईं, जिन पर सब्सिडी का बोझ था। सब्सिडी की बढ़ती लागत (इस साल के लिए अनुमान तीन लाख करोड़ रुपये है) को ज्यादा समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था के बुनियादी आधार (घाटा, कर्ज और ब्याज दरें) पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। मतदान खत्म होने के बाद से ही युद्ध कर, सुरक्षा कर, पूंजी के लेन-देन पर रोक और ऐसी ही कई दूसरी बातों को लेकर चर्चा जोरों पर है। रुपया में गिरावट के कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है—साल के पहले चार महीनों में उनकी कुल बिक्री दो लाख करोड़ रुपये रही, जो पूरे 2025 में हुई उनकी बिक्री से भी ज्यादा है।

प्रधानमंत्री के बचत पर दिए गए उपदेश के बाद, सोमवार को शेयर बाजारों को जोरदार झटका लगा, और रुपये में भी भारी गिरावट आई। रुपये में गिरावट के कारण लोग सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं, जिसके चलते रुपये में और गिरावट आती है। रुपये की मौजूदा स्थिति उसकी कमजोरी का कारण भी है और परिणाम भी। रुपये के सामने एक और खतरा यह है कि पिछले साल मिले 135 अरब डॉलर के रेमिटेंस (विदेश से आने वाले पैसे) की रफ्तार धीमी हो सकती है या यह कम हो सकता है। यदि खाड़ी देशों में रोजगार का सपना टूटने लगता है, तो इसका असर न केवल वहां से आने वाली रकम की मात्रा पर पड़ेगा, बल्कि रोजगार की तलाश करने वालों के लिए उपलब्ध विकल्पों पर भी पड़ेगा। इस संघर्ष ने हजारों विनिर्माण इकाइयों को उत्पादन के लिए जरूरी गैस से महरूम कर दिया है—कई इकाइयां अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। एलपीजी की कमी के चलते मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। ऊर्जा संकट ऐसे समय में आया है, जब रोजगार बाजार पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एआई के आने के बाद आईटी सेवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों में अब नई भर्तियां धीमी हो गई हैं, जबकि छंटनी की रफ्तार तेज हो गई है। वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल लर्निंग अपनाने की अपील से पता चलता है कि यह एक बड़ा संकट है और इसके लिए अर्थव्यवस्था में बड़े बदलावों की जरूरत है। युद्ध के परिणामों से वैश्विक व्यवस्था को ढांचागत क्षति पहुंच रही है। राजनीतिक वर्ग को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम ऐसे दौर में अपना रास्ता कैसे तय करें, जहां अनिश्चितता ही एकमात्र स्थिर सत्य है।

मुख्यमंत्री ने रायगढ़ को दी 102 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

जनता का विश्वास ही सरकार की बड़ी ताकतः साय

रायपुर. सुशासन तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले के कुसमुरा में आयोजित सभा में जिलेवासियों को 102 करोड़ 93 लाख 24 हजार रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कुल 24 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 33 करोड़ 98 लाख 47 हजार रुपए लागत के 13 कार्यों का लोकार्पण तथा 68 करोड़ 94 लाख 77 हजार रुपए लागत के 11 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है और अब जनता स्वयं परिवर्तन और विकास को महसूस कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायगढ़ से उनका आत्मीय रिश्ता वर्षों पुराना है और यहां की जनता ने उन्हें हमेशा परिवार के सदस्य की तरह स्नेह दिया है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास, संवाद और समाधान का सशक्त माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि 1 मई से 10 जून तक आयोजित सुशासन तिहार के माध्यम से प्रदेशभर में आम नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए चलाए गए विशेष अभियान से हजारों लोगों को राहत मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है तथा 13 लाख किसानों को 3716 करोड़ रुपए का बकाया बोनस दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है और सरकार अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि आगामी समय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रारंभ की जाएगी, जिससे आम नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और समय-सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की मांगों पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ग्राम सूपा, घुघुवा, पुटकापुरी, तारापुर, उसरौट और काशीचुआं को जोड़ने वाली सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की घोषणा की। इसके साथ ही कुसमुरा में महतारी सदन निर्माण, धनागर सोसायटी के अंतर्गत खाद्य भंडारण हेतु गोदाम निर्माण तथा उप स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन की दिशा में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

जनदर्शन में कैबिनेट मंत्री ने सुनीं आम जनता की समस्या

रायपुर। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने लखनपुर स्थित अपने निज निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों, महिलाओं और नागरिकों ने सड़क, बिजली, पेयजल, राजस्व प्रकरण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा हर शिकायत का निराकरण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना चाहिए।जनदर्शन के दौरान मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता और विकास को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। शासन की मंशा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी पात्र हितग्राही को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में अधोसंरचना विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश देते हुए कहा कि फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और जनता की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है और इस विश्वास को बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

सीएम हेल्पलाइन 1076 से आम जनता की शिकायतों का होगा समयबद्ध निराकरण

रायपुर। जशपुर में अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को मिलेगा नया सशक्त माध्यम

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रदेश के नागरिकों को शासकीय सेवाओं तक सरल पहुंच और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली छत्तीसगढ़ प्रारंभ की जा रही है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अंतर्गत संचालित इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने, शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत, सुलभ और विश्वसनीय मंच प्रदान करना है।

इसी क्रम में जशपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण सभी अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए और शिकायतों के समाधान में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार, अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू, सीएम हेल्पलाइन के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री हरिओम द्विवेदी, सभी एसडीएम तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण दल के प्रमुख श्री अनुराग दीवान ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन एक केंद्रीकृत और तकनीक आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिक फोन, व्हाट्सऐप, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और लिखित आवेदन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट टोकन नंबर प्रदान किया जाएगा, जिससे उसकी रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव होगी। उन्होंने बताया कि शिकायतों के समाधान के लिए चार स्तरीय तंत्र विकसित किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री के प्रवास की तैयारियों का उप मुख्यमंत्री शर्मा ने लिया जायज़ा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित बस्तर प्रवास को लेकर तैयारियों का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर से कार्यक्रम स्थल को जाने के लिए निजी वाहन के स्थान पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुरूप सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ पूल वाहन के रूप में बस से सफर किया। जगदलपुर विकासखंड के नेतानार स्थित शहीद गुण्डाधुर सेवा डेरा पहुंचकर उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सेवा डेरा परिसर में संचालित सेवा सेतु केंद्र, बैंक सखी केंद्र तथा महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित आर्थिक गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके कार्यों की जानकारी ली तथा स्वरोजगार और आजीविका संवर्धन के प्रयासों की सराहना की।निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में बेहतर कार्य कर रही हैं। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सेवा सेतु केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा स्थल का भी निरीक्षण किया तथा वहां साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, रंग-रोगन और आवश्यक सजावट सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर के महान जननायक शहीद गुंडाधुर की स्मृति से जुड़ा यह स्थल गौरव का प्रतीक है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं बेहतर और सुव्यवस्थित होनी चाहिए।

बस्तर के बच्चों की खेल प्रतिभा तराशने जल्द शुरू होगी अकादमी

रायपुर। बस्तर के बच्चों की खेल प्रतिभा और कौशल को तराशने खेल एवं युवा कल्याण विभाग जगदलपुर में जल्द ही नई अकादमी खोलने जा रहा है। यह बस्तर अंचल का पहला आवासीय खेल अकादमी होगा। यहां बालकों को एथलेटिक्स, फुटबॉल और आर्चरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अकादमी में प्रवेश के लिए विभाग द्वारा जल्द ही चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती तनुजा सलाम ने आज जगदलपुर पहुंचकर अकादमी शुरू करने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बस्तर के खेल अधिकारियों से चर्चा कर मौजूदा अधोसंरचनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने उपलब्ध आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, चयन ट्रायल की प्रक्रिया, विद्यालय सुविधा, वाहन व्यवस्था, खेल सामग्री तथा आवास सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने प्रस्तावित अकादमी भवन का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को खिलाड़ियों के लिए बेहतर वातावरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्रीमती सलाम ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ होने से स्थानीय प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे क्षेत्र के खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और पदक अर्जित कर सकेंगे। इस अकादमी से बस्तर के नैसर्गिक प्रतिभावान खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, डाइट, आधुनिक उपकरण, आवास, शिक्षा, बीमा, किट, इलाज, उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी आदि की सुविधा खेल विभाग से मिलेगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

मोदी की गलत नीतियों के कारण देश संकट में : बैज

रायपुर। पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामाग्री आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी कीमतो तथा बेतहाशा महंगाई के विरोध में कांग्रेस चार दिवसीय आंदोलन करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश के समस्त जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों में 17 मई 2026 से चार दिवसीय धरना, प्रदर्शन एवं आंदोलन किये जाने का निर्णय लिया है, इसके तहत 17 मई 2026 - पेट्रोल, डीजल की संकट व दाम बढ़ाये जाने के विरोध में पेट्रोल पम्पों के सामने, बढ़े मूल्यों को वापस लिये जाने की मांग को लेकर बैनर, स्लोगन एवं तख्ती लेकर प्रदर्शन किया जायेगा एवं पेट्रोल पम्पों में जनता से संवाद एवं चर्चा कर सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करें। 18 मई 2026 - खाद्य तेल एवं राशन सामाग्री की बढ़ती कीमतों को लेकर किराना बाजारों में प्रदर्शन एवं किराना व्यवसायियों एवं जनता से संवाद एवं चर्चा कर सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करें।19 मई 2026 - सोने की खरीदी पर रोक के आव्हान से सराफा व्यवसाय ठप्प होने व सोने-चांदी के व्यापारियों, कारीगरों एवं कर्मचारियों के रोजी-रोटी की सकट के विरोध में सराफा बाजारों में प्रदर्शन एवं सराफा व्यवसायियों सहित जनता से संवाद एवं चर्चा कर सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करें।

भीषण गर्मी में भाजपा सरकार बिजली कटौती कर रही: शुक्ला

रायपुर। गर्मी के मौसम में अघोषित बिजली की कटौती आम आदमी के लिये सरदर्द बन गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिजली के साथ भाजपा सरकार आने के बाद जनता को पूरे 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। सुबह 6 बजे बिजली काट दी जा रही है। पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। ढाई साल में विद्युत सरप्लस वाला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केंद्र बन गया है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बिजली दो-चार घंटे के लिये बंद न हो, रात में तो बिजली की स्थिति तो और भयावह हो जाती है, घंटो बिजली गोल हो जाती है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा से न सरकार संभल पा रहा और न ही व्यवस्थायें। सरकार एक तो पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही, ऊपर से उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ डाल रही है। प्रदेश के अनेक जिलों में तो पूरी रात बिजली कटौती हो रही है। मई माह में हर उपभोक्ता का बिजली बिल दो से तीन गुना ज्यादा आया है। कांग्रेस की सरकार के दौरान 24 घंटा बिजली की आपूर्ति होती थी। गर्मी के दिनों में मांग बढ़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली की खरीदी किया जाता था और आम जनता को 24 घंटा बिजली की आपूर्ति की जाती थी।

सरकार की मितव्ययिता सिर्फ ढोंगः ठाकुर

रायपुर। भाजपा सरकार के मितव्ययिता के आदेश को ढोंग करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार जब मितव्ययिता की बात कर रही है पेट्रोल, डीजल बचाने शासकीय कर्मचारियों को वर्क फार्म होम का निर्देश दे रही है। आम जनता से पेट्रोल, डीजल का कम उपयोग करने अपील कर रही है। सरकार के मंत्री अपने काफिले के वाहन में कमी का दावा कर रहे है। साइकिल चलाकर रील बना रहे है। ऐसे में सुशासन तिहार पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? सुशासन तिहार के नाम से रोज हेलीकॉप्टर उड़ाये जा रहे है। भीड़ लाने एवं अधिकारियों के तिहार में पहुँचने गाड़ियों में जो हजारों लीटर डीजल, पेट्रोल फूंके जा रहे है इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? सरकार के कथनी एवं करनी में अंतर है। जनता पेट्रोल, डीजल के लिए आधी रात से लाईन लग रही है। पेट्रोल पंप के बाहर नो स्टॉक का बोर्ड लगा है। सरकार तिहार मना रही है। जनता जानना चाहती है जब डीजल, पेट्रोल संकट है फिर सुशासन तिहार के आयोजन के लिए पेट्रोल, डीजल कहां से आ रहा है? ट्रक, ट्रैक्टर, बस सहित छोटे मंझौल वाहन स्वामी को पर्याप्त डीजल नहीं मिल रहा है। मोटर साइकिल के लिए मात्र 300 रु. एवं कार के लिए 1000 रु. तक पेट्रोल देने की सीमा तय कर दी गई है।

आकाशवाणी के 90 वर्ष पर भव्य वॉकथन का हुआ आयोजन

रायपुर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केन्द्र द्वारा भव्य वॉकथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आकाशवाणी के वर्तमान कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी, समाचार वाचक, श्रोता, युवा वर्ग तथा शहर के अनेक प्रमुख नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा, समाज में उसके योगदान तथा जनसंचार के क्षेत्र में उसकी विश्वसनीय भूमिका को स्मरण करना था।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक श्री संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक श्री रमेश जायभाये तथा माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख श्री अर्पित तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों और युवाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही।

महंत कॉलेज में दो दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

रायपुर। स्थानीय महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की प्रासंगिकता विषय पर आधारित दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 14 एवं 15 मई 2026 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा समकालीन शिक्षा व्यवस्था में उसके प्रभावों पर व्यापक विमर्श करना था। कार्यशाला में भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय शिक्षण मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रख्यात प्राध्यापक डॉ. अजय सिंह मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रासंगिकता पर अपना विस्तृत व्याख्यान देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा और नैतिक मूल्यों को आधुनिक शिक्षा से जोडने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह नीति विद्यार्थियों में रचनात्मकता, कौशल विकास, शोध प्रवृत्ति तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। साथ ही उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के मूल आधार से जोडने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन नहीं, बल्कि भारत को ज्ञान आधारित विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से भारतीय चिंतन, भाषा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

220 केवी धमधा-गैंदपुर की नई डबल सर्किट लाइन

पांच जिलों में विद्युत आपूर्ति के लिए तैयार की नई डबल सर्किट लाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विद्युत आपूर्ति क्षमता को बेहतर बनाने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पॉवर ग्रिड के 765 केवी उपकेंद्र धमधा से स्टेट ग्रिड के लिए 220 केवी गैंदपुर की नई डबल सर्किट लाइन को स्थापित कर ऊर्जीकृत कर लिया गया है। इस लाइन के ऊर्जीकृत होने से केंद्रीय ग्रिड से पॉवर प्राप्त करने की क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो सकेगी । साथ ही इससे पांच जिलों में विद्युत आपूर्ति और अधिक विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण होगी।

माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रदेश की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला के हाथों से इसे ऊर्जीकृत किया गया।

शुक्ला ने इस अवसर पर बताया कि दुर्ग जिले के धमधा-मेड़ेसरा स्थित पावर ग्रिड के 765/400/220 केवी उपकेंद्र से 220 केवी धमधाङ्कगेंदपुर ट्रांसमिशन लाइन का सफल चार्जिंग एवं सिंक्रोनाइजेशन कर दिया गया है।

इस डबल सर्किट लाइन के ऊर्जीकृत होने से 220 केवी चार बड़े उपकेंद्र गैंदपुर (कवर्धा), मुंगेली, बेमेतरा और सुहेला में बिजली का आदान-प्रदान बेहतर हो सकेगा। पहले इसके लिए 220 केवी की तीन लाइनें थी, वह अब बढ़कर पांच हो गई हैं।

इससे राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा व बलौदाबाजार-भाठापारा जिले में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। इससे धमधा-गैंदपुर लाइन में तकनीकी खराबी आने पर भी विद्युत आपूर्ति जारी रह सकेगी। यह नई लाइन औद्योगिक, कृषि एवं घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (लाइन) संजय पटेल, कार्यपालक निदेशक (पीसी एवं आरए) के. एस. मनोठिया, कार्यपालक निदेशक (ट्रांसमिशन) श्री वी. के. दीक्षित, मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट) श्री पी. गोसावी, मुख्य अभियंता (सब-स्टेशन) श्री अब्राहम वर्गीस, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री मनोज राय सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री दयाल दास बघेल ने बाल वैज्ञानिक सृष्टि और पीयूष को किया सम्मानित

रायपुर। प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत मुढ़ीपार में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। जहां विकासखंड शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी डडसेना के मार्गदर्शन व गौरव चंद्राकर के विशेष देखरेख में तैयार किया गया बाल वैज्ञानिक सृष्टि यदु पीएम श्री विद्यालय पिथौरा का मॉडल मल्टीपरपज स्मार्ट रोबोटिक्स एवं पियूष साहू सेंट फ्रांसिस विद्यालय पिथौरा का मॉडल सांपों की सुरक्षा वाला चारपाई का आगामी सितंबर माह 2026 में होने वाले राष्ट्रीय विज्ञान मेला दिल्ली के लिए चयनित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्य अतिथि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने बाल वैज्ञानिकों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, बसना विधायक डॉ संपत अग्रवाल, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह उपस्थित थे। इस उपलब्धि के लिए उषा पुरुषोत्तम धृतलहरे जनपद अध्यक्ष, ब्रह्मा पटेल जनपद उपाध्यक्ष, रामदुलारी सीताराम सिन्हा जिला पंचायत सभापति, बीएल देवांगन जिला शिक्षा अधिकारी ने बाल वैज्ञानिक सृष्टि और पीयूष और उनके मार्गदर्शन शिक्षक गौरव चंद्राकर को बधाई और शुभकामनाएं दी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.